

मोपाल

10 जुलाई 2024
बुधवार

आज का मौसम

 27 अधिकतम
23 न्यूनतम

बेबाक खबर हर दोपहर

दोपहर मेट्रो

Page-7

मप्र कैबिनेट ने दी मंजूरी, ऑनलाइन हो जाएगी विधानसभा...

पेपरलेस विस के लिए अब प्रोजेक्ट ई-विधान, सरकार के लिए नया विमान



मोपाल, दोपहर मेट्रो।

आज मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें विधानसभा को हाईटेक बनाने के लिए कैबिनेट में नेशनल ई-विधान प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके चलते अब करीब 23 करोड़ के खर्च से सभी काम विस में अब ऑनलाइन होंगे। ई विधान परियोजना की मंजूरी मिलने और उसके लागू होने के बाद विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान पढ़े जाने वाले प्रश्न भी सभी सदस्यों को आनलाइन स्क्रीन पर नजर आएंगे। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्रालय, विधानसभा सचिवालय और संसदीय कार्य विभाग के बीच अनुबंध भी हो चुका है। कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस परियोजना में 23 करोड़ से अधिक खर्च आ सकता है। इसके अलावा आज कैबिनेट ने नया विमान खरीदने का भी निर्णय लिया है। यह करीब 233 करोड़ रुपये का होगा और कनाडा की कंपनी से खरीदा जाएगा। दरअसल राज्य सरकार का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सरकार के पास विमान की कमी हो गई थी। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर और उज्जैन संभाग के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। सीएम ने विधायकों से विकास का रोड मैप मांगा है। इसके बाद भोपाल, नर्मदापुरम संभाग की बैठक होगी।

अमरवाड़ा में आज प्रतिष्ठा की जंग, जमकर हो रहा मतदान



मोपाल/छिंदवाड़ा, एजेंसी।

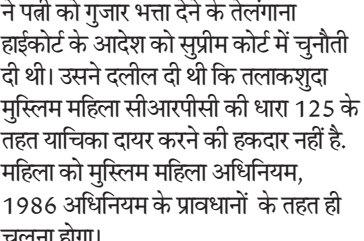
आज मप्र की अमरवाड़ा समेत समेत 7 राज्यों की तेरह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। अमरवाड़ा उपचुनाव मप्र में भाजपा के पिछले प्रदर्शन और कांग्रेस के कमलनाथ फैक्टर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। आज बारिश की आशंका के बीच वोटर सुबह ही वोट डालने के लिए वोटर घरों से निकल गये थे। दोपहर तक यहां करीब 44 फीसद मतदान हुआ है। पिछले विधान सभा चुनाव में यहां 82 प्रतिशत मतदान हुआ था और कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश शाह जीते थे। इस बार वे भाजपा के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने धीरेन शाह को उतारा है। खास बात यह है कि अमरवाड़ा शुरू से ही जमकर मतदान के मामले में अग्रेसर रहा है। यह आदिवासी बहुल इलाका है। इस सीट पर जीत के लिये भाजपा की तरफ से सीएम मोहन यादव, वीड्री शर्मा समेत कई नेता ताकत डोंक चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने तीन दिन यहां डेरा डाला था। बाद में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, नकुलनाथ ने यहां प्रचार की कमान संभाली थी और आखिरी दिन तक ताकत डोंकी थी। इस चुनाव के परिणाम मप्र कांग्रेस के मौजूदा निजाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

धारा 125... मुस्लिम महिला भी पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार

नई दिल्ली, एजेंसी।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि मुस्लिम महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते के लिए अपने पति के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन गॉज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला धरण-पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि यह धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। हालांकि, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन गॉज मसीह ने अलग-अलग फैसला सुनाया लेकिन दोनों की राय समान है। दरअसल, अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम



ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा।

शेयर बाजार में कोहराम सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम

मुंबई, एजेंसी।

आज भारतीय शेयर बाजार में जमकर गिरावट से हाहाकार के हालात हैं तथा निवेशकों में बेचैनी है। बीते कारोबारी दिन जोरदार तेजी थी तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 80,000 के स्तर के पार क्लोज हुआ था। मगर आज शेयर बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों बाद सेंसेक्स धराशायी हो गया। हालांकि सेंसेक्स ने जैसे ही कारोबार शुरू किया तो अपना नया ऑल टाइम रिकॉर्ड लेवल छू लिया मगर अगले ही पल बिखरने लगा और 900 अंक से ज्यादा फिसल गया। यही हाल निफ्टी भी है। सेंसेक्स की तरह ही आज



निफ्टी भी बुरी तरह टूटा है। एनएसई इंडेक्स ने अपने पिछले बंद 24,433 की तुलना में तेजी के साथ 24,459.85 के लेवल पर कारोबार शुरू किया था और कुछ ही मिनटों में ये सेंसेक्स के कदम से कदम मिलते हुए धड़ाम हो गया। यह 1.04 फीसदी फिसलकर 24,180.25 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था।

मेट्रो एंकर

मध्यप्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन की जद्दोजहद निर्णायक मोड़ पर...

समावेशी फार्मूला व शादी-रेस के घोड़ों में फर्क की चुनौती

आशीष दुबे/भोपाल



मप्र कांग्रेस की छह महीने से अटकी कार्यकारिणी का गठन करीब है, यदि कोई बड़ा पेंच नहीं आया तो कार्यकारिणी का ऐलान इसी महीने होगा। इसमें अध्यक्ष जीतू पटवारी के समक्ष अब 'शादी के घोड़े और मैदानी घोड़ों' के बीच फर्क करने का चैलेंज सबसे बड़ा है। माना जा रहा है कि कार्यकारिणी के लिए नए और पुराने चेहरों का मिश्रण तैयार किया जा रहा है। इनमें कुछ ऐसे भी पुराने चेहरे हैं जो लंबे अरसे से दरकिनार हैं। वहीं कुछ ऐसे पुराने चेहरे भी इस फार्मूले में फिट होने की जुगाड़ में हैं, जो लंबे समय से हर कार्यकारिणी में जगह पाते रहे हैं, हालांकि परफार्मेंस व गुटीय निष्ठा के मामले में इनमें से कईयों पर बड़े सवाल भी हैं। दरअसल, कांग्रेस हाईकमान ने मप्र, छत्तीसगढ़

ओडिशा, हिमाचल, गुजरात और उत्तराखंड राज्यों की पीसीसी के आकार-प्रकार के लिए खास पैमाने तय किए हैं। क्योंकि इन्हीं राज्यों के कमजोर प्रदर्शन से कांग्रेस दिल्ली की रेस में चूकी है। लिहाजा राज्यों के

प्रभारी महासचिव व सचिवों से एक ताजा रिपोर्ट मांगी गई हैं। एआईसीसी सूत्रों की मानें तो हाईकमान मप्र जैसे कुछ राज्यों में कड़े फैसले लेना चाहता है, इसमें गुटबाजी खत्म करना और असहयोग पर कड़ी नजर

रखना शामिल है। अब हाईकमान की कसौटियों पर प्रदेश अध्यक्षों भी रहेंगे। निश्चित समयावधि में अध्यक्षों का भी आकलन होगा, ताकि बड़ा या कड़ा फैसला लिया जा सके। मप्र में पहले पृथ्वीराज चव्हाण वाली फैक्ट फाईडिंग कमटी फिर दो दिन का प्रभारी महासचिव का मैरथन मंथन इसी से जुड़ा है। खास यह कि इस मंथन मैदानी क्षमता दिखाने वाले चेहरे भी तलाशे जा रहे हैं। एक सूत्र का कहना है कि कार्यकारिणी न तो जंबो रहेगी और न ही माइक्रो होगी। बल्कि संतुलित होगी।

ड्राइवर की झपकी से गई 18 जान, भीषण सड़क हादसा



कानपुर, एजेंसी।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बेहटा मुजावर क्षेत्र के गड़ा गांव के पास बुधवार सुबह 5.30 बजे हुआ। हादसे में एक बच्चे की भी मौत हुई है। बस बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी। चालक को झपकी आने से हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर बेहटामुजावर थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए बांगरमऊ सीएचसी में भर्ती कराया। वहीं शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

बच्चों के भीख मांगने पर सख्त कोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में बच्चों द्वारा भीख मांगने की घटनाओं से निपटने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का प्रचार करें। बच्चों के भीख मांगने के खिलाफ एक जनहित याचिका पर विचार कर रही एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडला वाली बेंच को दिल्ली सरकार ने बताया कि कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन पर ऐसी घटना की सूचना दे सकता है और इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। सरकार ने बताया कि इस सिस्टम के तहत बच्चे को परामर्श दिया जाएगा और उसे उसके पैतृक घर या चाइल्ड केयर होम में भेजा जाएगा।



बच्चों की जानकारी जुटाने निकले अमले को मिले दो-दो पत्नियों वाले शिक्षक

डिंडोरी, एजेंसी।

मप्र के डिंडोरी जिले से एक अजब रिपोर्ट सुर्खी में है। टू चाइल्ड पॉलिसी के तहत तीन बच्चों वाले सरकारी कर्मियों की जानकारी जुटाने में जुटे अमले को यह चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। खबरों के मुताबिक पहली बार सरकार को दो पत्नियों वाले शिक्षकों की भी इसमें जानकारी मिली है। डिंडोरी के कुछ हिस्सों में सर्वे में आठ शिक्षक ऐसे मिले हैं, जिनकी दो पत्नियां हैं। कुल 29 शिक्षकों और कर्मचारियों की यह रिपोर्ट है। इनमें ऐसे शिक्षक भी हैं जो शराब पीकर बच्चों को पढ़ाने

के लिए स्कूल आते हैं। कुछ बिना बताए गैरहाजिर भी रहते हैं। जांच के दौरान यह भी बात सामने आई कि एक शिक्षक पिछले 19 साल से गायब हैं। वह स्कूल ही नहीं आए हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे शिक्षक भी थे जो लगातार स्कूल से लापता हो मिलते हैं। तीन बच्चों वाले शिक्षकों की भी जानकारी सामने आई है। इस बारे में स्थानीय अफसरों का कहना है कि हम ऐसी सूची इसलिए तैयार करवा रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन और अन्य चीजों को लेकर कोई विवाद नहीं हो। हमें जो सूची मिली है, उसकी जांच कराएंगे।

आज का कार्टून



ये कैसी खबर है... बिहार में युजफ्ट और पुल बेदिली में कूपर आरंभ हुआ करती...

कार्रवाई के बजाए क्लीनचिट क्यों, भड़की मायावती

लखनऊ। बसपा चीफ मायावती ने हाथरस भगदड़ मामले की इन्क़ायरी के लिए गठित विशेष जांच दल की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने एक्स पर लिखा है कि स्टूडन की यह रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं है, बल्कि राजनीति से प्रेरित ज्यादा है। मुख्य आयोजक सुरजपाल उर्फ 'भोले बाबा' की भूमिका के बारे में एसआईटी की खामोशी भी चिंता का कारण है। सुरजपाल पर कड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास किया गया है। 121 निर्दोष महिलाओं व बच्चों आदि की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता-जागता प्रमाण है। मायावती ने कहा कि एसआईटी द्वारा सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है, यह अति-दुःखद है।

अब 13 साल से कम उम्र के बच्चों को भी 9वीं में प्रवेश का रास्ता साफ

छात्रों की व्यवहारिक कठिनाई दूर की

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

छात्रों की कठिनाईयों को समझते हुए अब स्कूलों में नौवीं कक्षा में 13 साल से भी कम उम्र के विद्यार्थियों का प्रवेश देने का रास्ता साफ हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को नौवीं के नामांकन में उम्र के बंधन में छूट दे दी है। शासन ने पिछले साल के नियम लागू कर दिए हैं। यह नियम सिर्फ सत्र 2024-25 के लिए मान्य होंगे। इसके मुताबिक अब 13 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नौवीं में नामांकन हो सकेगा। पिछले साल भी माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) ने नौवीं में 13 वर्ष की उम्र का नियम



लागू किया था, जिसे राज्य शासन ने नियमों में शिथिलता देते हुए छूट दी थी। दरअसल मप्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष की है। इसके अनुसार माशिम भी नौवीं के नामांकन में न्यूनतम आयु 13 वर्ष या उससे ज्यादा की है, लेकिन कई विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में आठवीं तक निरंतर पढ़ते हुए वर्तमान में 12 साल उम्र तक के भी थे। वर्तमान में माशिम में नौवीं के नामांकन का कार्य चल रहा है। जिसमें एक अप्रैल की स्थिति में न्यूनतम आयु 13 वर्ष होना चाहिए। इससे हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का अभी तक नामांकन नहीं हो पाया। मामले में माशिम ने मप्र शासन व राज्य शिक्षा केंद्र को प्रवेश के नियम शासन को भेज दिए थे। जिसमें बताया गया है कि शासन ने पहली में प्रवेश की न्यूनतम आयु छह

साल निर्धारित की है। इसके अनुसार मंडल में छह प्लस आठ यानि 14 साल की उम्र में नौवीं नामांकन हो रहा था। माशिम ने पिछले वर्षों के नियम को देखते हुए नौवीं में नामांकन की न्यूनतम आयु 13 वर्ष की है। शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नौवीं में नामांकन पिछले साल के नियमों के आधार पर इस वर्ष सत्र 2024-25 में होंगे। यह नियम सिर्फ वर्तमान सत्र के लिए मान्य किए गए हैं। नौवीं में नामांकन के लिए माशिम ने प्रवेश नीति जारी की, जिसमें 13 वर्ष की आयु से कम विद्यार्थियों को नौवीं में प्रवेश देने से मना कर दिया गया। उम्र के बंधन पर उठे विवाद पर लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त की तरफ से राज्य शासन के पास प्रस्ताव गया। इस प्रस्ताव पर शासन ने नौवीं में नामांकन में उम्र के बंधन की छूट दी है।

रेलवे ने कहा-मुसाफिर पूछताछ के बाद यात्रा शुरू करें

पटरियों पर काम के चलते कई ट्रेनों का बदला रास्ता

परिवर्तित मार्ग वाया वसई रोड-सूरत-वडोदरा-रतलाम-भोपाल से जाएगी

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

मध्य रेल के भुसावल मंडल के भुसावल-खंडवा खंड के बीच गेज परिवर्तन के चलते 19 यात्री ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि असुविधा से बचने के लिए रेलवे की अधिकृत पूछताछ सेवा एनटीईएस, 139 से ट्रेन की सही स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रियों को अपनी यात्रा प्रारंभ करना चाहिये। फिलहाल किये बदलाव के मुताबिक 11057 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-अमृतसर एक्सप्रेस 14 से 21 जुलाई तक प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान कर अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग वाया वसई रोड-सूरत-वडोदरा-रतलाम-भोपाल होते हुए गंतव्य को जाएगी। 11058 अमृतसर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस 14 से 21 जुलाई तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान कर परिवर्तित मार्ग वाया भोपाल-रतलाम-वडोदरा-सूरत-वसई रोड होते हुए गंतव्य को जाएगी।



इसी प्रकार 12361 आसनसोल-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस 21 जुलाई को इटारसी-नरखेड-बडनेरा-भुसावल जाएगी। 12485 नांदेड-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस 22 जुलाई को परिवर्तित मार्ग वाया पूर्णा-अकोला-बडनेरा-नरखेड-इटारसी होते हुए जायेगी। 12618 निजामुद्दीन-एर्नाकुलम एक्सप्रेस 22 जुलाई को वाया इटारसी-नरखेड-बडनेरा-भुसावल होते हुए जाएगी। 12627 बैंगलोर-नयी दिल्ली एक्सप्रेस 21 जुलाई भुसावल-बडनेरा-नरखेड-इटारसी होते हुए

जाएगी। 12715 नांदेड-अमृतसर एक्सप्रेस 22 जुलाई को वाया पूर्णा-अकोला-बडनेरा-नरखेड-इटारसी होते हुए जाएगी। 12753 नांदेड-निजामुद्दीन एक्सप्रेस 16 जुलाई को पूर्णा-अकोला-भुसावल-बडनेरा-नरखेड-इटारसी होते हुए गंतव्य को जाएगी। 12754 निजामुद्दीन-नांदेड एक्सप्रेस 17 जुलाई को इटारसी-नरखेड-बडनेरा-अकोला-परभणी होते हुए जाएगी। 12782 निजामुद्दीन-मैसूर एक्सप्रेस 22 जुलाई को इटारसी-नरखेड-

बडनेरा-भुसावल होते जाएगी। 17019 हिसार-हैदराबाद एक्सप्रेस 16 जुलाई को रतलाम-वडोदरा-सूरत-जलगांव होते हुए व 17020 हैदराबाद-हिसार एक्सप्रेस 20 जुलाई को जलगांव-सूरत-वडोदरा-रतलाम होते हुए जाएगी। 19435 अहमदाबाद-आसनसोल एक्सप्रेस 18 जुलाई को वाया वसई रोड-सूरत-वडोदरा-रतलाम-भोपाल होते और 19436 आसनसोल-अहमदाबाद एक्सप्रेस 20 जुलाई को प्रारंभिक स्टेशन से वाया भोपाल-रतलाम-वडोदरा-सूरत-वसई रोड होते हुए गंतव्य को जाएगी। 19483 अहमदाबाद-बरोनी एक्सप्रेस 15 से 22 जुलाई तक वाया सूरत-वडोदरा-रतलाम-भोपाल होते हुए तथा 19484 बरोनी-अहमदाबाद एक्सप्रेस 14 से 20 जुलाई तक भोपाल-रतलाम-वडोदरा-सूरत होते हुए जाएगी। 20104 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 21 जुलाई को इटारसी-नरखेड-बडनेरा-भुसावल होते हुए गंतव्य को जाएगी।

ग्वालियर से ट्रेन से बुलाया, कोई नहीं आया लेने

12 क्विंटल मावा जब्त, जांच के लिए भेजे सैंपल



भोपाल, दोपहर मेट्रो।

मावा की मांग को पूरा करने के लिये ग्वालियर से मंगाया गया 40 क्विंटल मावा शक के दायरे में है। यह ट्रेन से भोपाल लाया गया। इसमें से 12 क्विंटल मावा को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बजरिया स्थित जीबी कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने से जब्त कर लिया। यह मावा व्यापारियों को सप्लाई किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक दूध सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अफसरों ने मावा तब पकड़ा, जब रेलवे स्टेशन से मावा व्यापारियों को डिलीवरी देने के लिए ले जाया जा रहा था। अमले ने पकड़े गए मावा के सैंपल लिए हैं। इन्हें जांच के लिए स्ट्रीट फूड लैबोरेट्री भेजा जाएगा। वहीं, भोपाल रेलवे स्टेशन

परिसर स्थित जीआरपी थाने के बाहर रखे 28 क्विंटल मावा की जांच के लिए रेलवे के फूड सेफ्टी ऑफिसर को ग्वालियर से भोपाल सप्लाई हुए मावा की जानकारी दी है। खाद्य सुरक्षा एवं प्रशासन अमले ने ग्वालियर से आए मावा की सैंपलिंग की कार्रवाई तड़के 5 बजे शुरू की थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक पकड़े गए मावा को क्लेम करने के लिए अभी तक भोपाल का कोई व्यापारी सामने नहीं आया है। इस वजह से मावा और उसे सप्लाई करने के लिए तैनात किए लोडिंग ऑटो को रोकना पड़ा है। पकड़े गए मावे की डिलीवरी लेने वाले व्यापारियों के सामने आने पर संबंधित मावे का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा।

अब कॉलेजों में नया ड्रेस कोड, पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज से होगी शुरुआत

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

प्रदेश के कॉलेजों में छात्र-छात्राओं के लिए ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेजों से होगी, जिनमें इसी शिक्षा सत्र से ड्रेस कोड लागू किया जा सकता है। बाद में यह व्यवस्था अन्य कॉलेजों में भी अपनाई जाएगी। इस संदर्भ में विभिन्न वर्गों की राय लेते हुए सहमति बनाने के प्रयास चल रहे हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंंदर सिंह परमार ने इस बात की जानकारी दी। इसी सत्र से होगी शुरुआत: उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि जब देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई तब इसे लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने प्रदेश के 55 जिला केंद्रों में उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित



करने का निर्णय लिया है। 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर से इसका शुभारंभ करेंगे। मंत्री परमार ने आगे कहा कि गणवेश को लेकर विचार चल रहा है, हम आने वाले समय में एक सहमति बनाकर गणवेश लागू करने की कोशिश करेंगे। सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक आदर्श ड्रेस कोड लागू करेंगे जिससे किसी वर्ग को उससे आपत्ति न हो।

बाहरी तत्वों पर लगेगा अंकुश: उन्होंने कहा कि हम समाज के सभी वर्गों, विद्यार्थियों के साथ कॉलेज में सकारात्मक वातावरण बनाते हुए कॉलेज की पहचान, समानता बताते हुए और उन कॉलेज में जो बाहर के तत्व आते हैं उनपर अंकुश लगाते हुए हम ड्रेस कोड लागू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी की इसपर सहमति होगी और एक सकारात्मक परिणाम आएगा।

एक हजार बच्चों ने की हनुमानजी की स्तुति

संस्कार में संगीतमय चालीसा पाठ की परंपरा

हिरदाराम नगर, दोपहर मेट्रो।

संस्कार विद्यालय में हर मंगलवार को प्रार्थना सभा में संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ प्रारम्भ किया था। इसी कड़ी में आज मंगलवार को मुख्य अतिथि भाजपा नेता कैलाश मिश्रा, संस्था के अध्यक्ष सुशील वासवानी, सचिव बसंत चेलानी बच्चों के साथ चालीसा पाठ किया। एक हजार बच्चों ने स्वरबद्ध हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस अवसर चेलानी ने कहा कि विद्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक मंगलवार को होता है और हम प्रत्येक महीने में चार से पांच बार हनुमान जी का नाम लेते हैं। वासवानी ने कहा कि संस्कार स्कूल का प्रांगण हर मंगलवार को श्रीराम भक्त हनुमानजी की वंदना करता है। अतिथि कैलाश मिश्रा ने कहा कि हनुमानजी का आशीर्वाद और कृपा हम



सब पर इसी तरह बनी रहे। शायद भोपाल के अन्दर ये पहला स्कूल होगा जहां हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ

होता है। हनुमान जी बल और बुद्धि के देवता हैं। उनका पाठ करने से बल एवं बुद्धि का विकास होता है।

मेट्रो एंकर

मिठी और नवनिध में अग्नि सुरक्षा सत्र

छात्र- छात्राओं ने जाना कैसे बुझाते हैं आग

हिरदाराम नगर, दोपहर मेट्रो।

शहीद हेमू कालाणी एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचालित मिठी गोबिंदराम पब्लिक स्कूल एवं नवनिध गर्ल्स स्कूल में अग्नि सुरक्षा सत्र के आयोजन किए गए। अलग-अलग कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा के महत्व, आग को रोकने के उपाय विशेषज्ञों ने बताया।

कार्यक्रमों में अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञ शक्ति कुमार तिवारी ने अग्नि सुरक्षा का महत्व, स्कूलों में आग लगने के सामान्य कारण, अग्नि सुरक्षा नियमों और मानकों का अवलोकन किया। उन्होंने न केवल व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया। जहाँ उन्होंने अग्निशामक यंत्र के उपयोग का प्रदर्शन किया और एक



अभ्यास सत्र भी दिया।। कार्यक्रमों में स्टूडेंट्स को संभावित अग्नि खतरों और आग को रोकने में सतर्कता के महत्व के बारे में बेहतर समझ प्राप्त हुई,

साथ ही उन्होंने और कर्मचारियों ने अग्निशामक यंत्रों और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना भी सीखा। विद्यार्थियों और कर्मचारियों ने सत्र के

बाद अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे अग्नि संबंधित आपात स्थिति का जवाब देने की अपनी क्षमता में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते

हैं। सुधार के लिए दिए गए सुझावों में लगातार व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र, विज्ञान प्रयोगशालाओं और अन्य विशेष क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा पर अतिरिक्त ध्यान देना सम्मिलित रहा। मिठी के प्राचार्य अजय बहादुर सिंह एवं नवनिध की प्राचार्या अमृता मोटवानी ने कहा कि अग्नि सुरक्षा उपाय सत्र हमारे स्कूल समुदाय की सुरक्षा और तैयारी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। अग्नि सुरक्षा शिक्षा को प्राथमिकता देना और अपने अभ्यासों को नियमित रूप से अपडेट करना जारी रखते हुए, हम सभी के लिए एक सुरक्षित शिक्षण वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। कार्यक्रम में कोर्डिनेटर, शिक्षक-शिक्षिकाएँ, ऑफिस स्टॉफ एवं छात्रगण उपस्थित रहे।



हिरदाराम नगर। नवनिध हसोमल लखानी पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने पौधारोपण किया। साथ ही 'अपने आस-पास को हरा-भरा बनाओ, अपने जीवन को सुंदर बनाओ।' का संदेश दिया। संस्था द्वारा हर साल बारिश में पौधारोपण अभियान चलाया जाता है। संत सिद्धभाऊजी विद्यार्थियों को एलोवेरा एवं तुलसी के पौधे उपहार में देते हैं। उसी कड़ी में नवनिध की छात्राओं ने अपने घरों व उद्यानों में नए-नए पौधे रोपित कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। यंत्रम में संस्था के सचिव घनश्याम बलूचंदानी, प्राचार्य अमृता मोटवानी, उप्राचार्य रेखा केवलानी, कोऑर्डिनेटर एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भी विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर प्रकृति के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन किया।

सीएम की अफसरों को दो टूक विधायकों के साथ समन्वय बनाकर चलें



पांच साल के विकास के रोडमैप पर चर्चा

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संभागवार भाजपा विधायकों से चर्चा कर विकास कार्य के साथ ही नौकरशाही को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय का पाठ पढ़ना शुरू किया है। इसी कड़ी की दूसरी बैठक में बीती रात रीवा और शहडोल संभाग के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। इस मौके पर दोनों संभाग के मैदानी व प्रभारी पुलिस प्रशासन अफसर मौजूद थे। संभाग के विधायकों से मुख्यमंत्री ने पांच साल का अपने क्षेत्र का विकास का रोडमैप देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक एक योजनाबद्ध तरीके से काम करें और समयसीमा में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करें। मुख्यमंत्री निवास पर अफसरों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में उन्होंने कहा, अफसर क्षेत्रीय विधायकों से समन्वय बना कर रखें और विकास के कार्यों में उनकी राय जरूर लें। बैठक में विधायकों ने अब तक विकास कार्यों के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों और उसमें आ रही कठिनाइयों के बारे में भी बताया। सामूहिक रूप से हुई इस बैठक में सीएम ने एक-एक विधायक से उनके क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों और लोकसभा चुनाव के अनुभव के बारे में भी बात की। मुख्यमंत्री इसके पूर्व ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह की बैठक कर चुके हैं। वे आज जबलपुर और उज्जैन संभाग के विधायकों से चर्चा करेंगे। इसके बाद भोपाल और नर्मदापुरम और सबसे अंत में इंदौर संभाग के विधायकों से मुख्यमंत्री की चर्चा होगी। बैठक के दौरान कुछ विधायक पांच बार के सांसद गणेश सिंह का पत्र लेकर आए, जिसमें उचेहरा का रेलवे फाटक बंद होने से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी का जिक्र है। गणेश सिंह ने इस पत्र में लिखा है कि रेलवे और राज्य सरकार के बीच समन्वय नहीं होने से यह रेलवे फाटक बंद हो गया है।

‘उमंग’ से 21 लाख छात्र-छात्राओं को जोड़ा

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

स्कूल शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संयुक्त रूप से मिलकर उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम समस्त हाई एवं हाई सेकेण्डरी स्कूलों में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम से छात्र-छात्राओं में जीवन कौशल को विकसित करना ताकि वे अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें और बेहतर स्वास्थ्य के लिये उचित निर्णय ले सकें। यह कार्यक्रम प्रदेश के 9 हजार 306 विद्यालयों में संचालित हो रहा है और इसका फायदा 21 लाख छात्र-छात्राओं को मिल रहा है। उमंग कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिये 52 राज्य स्तरीय, जिलास्तर पर 427 और प्रत्येक स्कूल में 2 शिक्षकों को आरोग्य दूत बनाया गया है।

अब सारथी और वाहन अटके, आरटीओ सर्वर में फिर उभरी तकनीकी बाधा

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

आरटीओ संबंधी कार्य बार-बार किसी न किसी वजह से लगातार अटक रहे हैं। अब वजह बनी है एनआइसी का पोर्टल परिवहन सारथी और वाहन। यह बार बार अटक जाता है। इससे कभी ड्राइविंग लाइसेंस के आनलाइन आवेदन अटक जाते हैं तो कभी वाहनों के पंजीयन की प्रक्रिया नहीं होती है। वाहन डीलरों की ओर से पंजीयनों की फाइल आरटीओ भेज जाती हैं, लेकिन यहां पर पंजीयन कार्ड नहीं बन पाते हैं। हालां ही में आरटीओ में लाइसेंस व पंजीयन कार्ड के प्रिंट का काम देख रही स्मार्टचिप कंपनी ने टेंडर नवीनीकरण नहीं होने से काम बंद कर दिया था। इससे आरटीओ काम नहीं हुए थे। इसी तरह फिटनेस के कार्य भी प्रभावित होते हैं।

बीते तीन महीनों से निरंतर यह समस्या बनी हुई है। आरटीओ में हर दिन एक हजार से अधिक लोग परमनेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वाहनों के पंजीयन, परमिट, फिटनेस, वाहनों के स्थानांतरण सहित अन्य कार्य नहीं



होते हैं। जब लोग आरटीओ में सर्वर डाउन व बंद हो जाने की शिकायत करते हैं तो जवाब मिलता है कि परिवहन सारथी व वाहन-चार के एनआइसी के हैं, इसलिए एनआइसी के अधिकारी ही बता पाएंगे। सबसे अधिक समस्या सोमवार को आती है, जब शनिवार व रविवार को अवकाश होने के बाद एक साथ कई लोग आरटीओ लोग पहुंचते हैं।

मेट्रो एंकर

प्रावधानित और प्रगतिरत् निर्माण कार्यों की समीक्षा

उप-मुख्यमंत्री शुक्ल बोले- समय-सीमा में गुणवत्ता से निर्माण कार्यों को पूर्ण करें

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय प्रावधान अनुसार और प्रगतिरत् निर्माण कार्यों की कार्य योजना की वृहद समीक्षा की। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य संस्थानों, नर्सिंग कॉलेज एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के नवीन निर्माण कार्यों के साथ उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के विभिन्न चरणों की भी समीक्षा की। उप-मुख्यमंत्री शुक्ल ने निर्देश दिये कि समस्त गतिविधियों को समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाये। उप-मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि औपचारिकताओं की कमी से कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए।

3 हजार 555 निर्माण कार्य प्रावधानित और प्रगति: उप-मुख्यमंत्री ने केंद्र से समन्वय वाले आवश्यक विषयों को रेखांकित करने के लिए कहा ताकि केंद्र स्तर से चर्चा कर उनका शीघ्र निराकरण किया जा सके। वर्तमान में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग अन्तर्गत 3 हजार 555 निर्माण कार्य प्रावधानित और प्रगतिरत् हैं। इनमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 2 हजार 782, म.प्र. भवन विकास निगम द्वारा 72, लोक निर्माण विभाग द्वारा 17,



म.प्र. हाउसिंग बोर्ड द्वारा 263, पीआईयू द्वारा 385, म.प्र. पुलिस हाउसिंग द्वारा 34, ब्रिज एंड रूफ द्वारा 2 निर्माण कार्य किये जा रहे हैं।

समय-सीमा में भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करें: उप-मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में पदों की भर्ती प्रक्रिया की प्रगति समीक्षा की और समय-सीमा में भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। बैठक में अपर

मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मो. सुलेमान, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विवेक कुमार पोरवाल, एम.डी. एनएचएम प्रियंका दास, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा तरुण पिथोड़े, अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा पंकज जैन सहित निर्माण विभाग के प्रतिनिधि और विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विभागों के कार्यालय शिफ्ट करने का मोहन सरकार का पहला बड़ा निर्णय

धार्मिक न्यास व मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का डायरेक्टोरेट ऑफिस उज्जैन में लगेगा

भोपाल, दोपहर मेट्रो। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के दो डायरेक्टोरेट कार्यालय उज्जैन से संचालित होंगे। सरकार ने दोनों कार्यालयों को शिफ्ट करने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। यह मोहन सरकार का विभाग शिफ्ट करने से जुड़ा पहला बड़ा निर्णय है।

सरकार ने इसके फायदे भी सोचे हैं, जिसको देखते हुए ये दोनों कार्यालय उज्जैन शिफ्ट किए गए। सरकार का मानना है कि वर्ष 2028 में सिंहस्थ है, जो उज्जैन समेत देशभर का बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। उक्त विभाग के दोनों ही डायरेक्टोरेट कार्यालय धर्म-कर्म से सीधे तात्कुर रखते हैं, जिनके अफसरों का उज्जैन में होना अनिवार्य है। हालांकि लोगों के मुताबिक यह व्यवस्था यदि स्थाई रहती है तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। जानकारों के



सरकार के निर्णय की बड़ी बात यह है कि दोनों डायरेक्टोरेट कार्यालय में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों को भी उज्जैन में ही सेवाएं देनी होंगी। जिसमें से कुछ की मुश्किलें बढ़ना तय है।

मुताबिक विभाग के प्रमुख सचिव भोपाल में ही बैठते हैं, जो आगे भी बैठते रहेंगे। ऐसे में मुख्य-मुख्य फाइलों को भोपाल ही लाना होगा। इनके लिए अलग व्यक्ति का इंतजाम करना होगा। इसमें समय भी लगेगा, इस तरह जो काम एक दिन में हो सकता था उसे एक से अधिक दिन लग सकते हैं। यही नहीं, फाइलों को एक से दूसरे शहरों में ले जाने के लिए आवागमन पर खर्च भी होगा।

नौरादेही रिजर्व से बाघ गायब, शिकार की आशंका

वन्यप्राणी विशेषज्ञ अजय दुबे की शिकायत पर जांच के आदेश

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

नौरादेही अर्थात्-वीरगंगा रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व से बाघ गायब है, कुछ के शिकार होने की आशंका है। यहां बाघों से जुड़े रिकार्ड में भी छेड़छाड़ गई है। वन विभाग ने इन सभी मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। बुधवार से जांच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट 7 दिन में वन मुख्यालय को भेजी जानी है।



यह है मामला- वन्यप्राणी विशेषज्ञ अजय दुबे ने मप्र के वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव को एक शिकायत की है। 27 जून को की गई उक्त शिकायत में उन्होंने नामजद दावे किए हैं कि बाघ, बाघिन और उनके कुछ शावक गायब हैं। इनमें से बाघिन एन-112 व एन-113 का हवाला भी दिया है। यह भी आरोप लगाए कि ये 2021 से ही

गायब है। यहां तक आरोप लगाए कि बाघिन एन-111 को रिकार्ड बदलकर एन-112 बता दिया गया है, जो कि गंधीर लापरवाही है। अजय दुबे ने आरोप लगाए कि रिजर्व में लकड़ी की अवैध कटाई की जा रही है। आसपास के क्षेत्रों में जमीन खरीदने वालों से ईको सेंसिटिव ज़ोन के नाम पर एनओसी देने के बदले मोटी रकम ली जा रही है। इन आरोपों का पत्र उन्होंने पीसीसीसीएफ वाइल्डलाइफ को भी भेजा है। शिकायत के बाद वन विभाग ने पोल खुलती देख जांच के आदेश जारी कर 7 दिन में नौरादेही रिजर्व के उप संचालक से जवाब रिपोर्ट मांगी है। एपीसीसीएफ समीता राजौरा ने जांच करने संबंधी आदेश मंगलवार को किए।



मुलाकात

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह-प्रभारी सतीश उपाध्याय ने केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह से दिल्ली में सौजन्य भेंट कर आभार व्यक्त किया। इस दौरान संगठन की गति देने के विषयों पर चर्चा हुई।

एमबीबीएस-बीडीएस काउंसिलिंग में अब दूसरे चरण में भी मिलेगा मौका

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों व डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस एवं बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग इसी माह शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने अभ्यर्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहले चरण में आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों को भी अब दूसरे चरण में अवसर मिल सकेगा। अभी तक उन्हें आपात्र कर दिया जाता था। जबकि पंजीयन में संशोधन का अवसर भी उन्हें एक बार दिया जाएगा, जो अभी तक नहीं मिलता था। पंजीयन में कोई गलती हो गई तो वह प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाते थे। इसके अतिरिक्त नई व्यवस्था यह की गई है कि मापअप चरण के पहले भी एक बार पंजीयन का अवसर दिया जाएगा। हाल में प्रवेश नियम जारी हुए हैं। यही नियम एमडी-एमएस और एमडीएस काउंसिलिंग में भी लागू होंगे। यह व्यवस्था भी की गई है कि विभिन्न श्रेणी में बाकी रहने वाली रिक्तियों को भरने के लिए दूसरे

महत्वपूर्ण बदलाव



की जगह अब पात्र श्रेणी में परिवर्तित किया जाएगा। नियम यह है कि अनुसूचित जाति (एससी) की सीटें बचने पर अनुसूचित जनजाति (एसटी) से भरी जाती हैं। इसी प्रकार एसटी की सीटें बचने पर एससी से भरने का नियम है। दोनों श्रेणी के उम्मीदवार नहीं मिलने पर इन्हें ओबीसी श्रेणी से भरा जाता है। इसी तरह से ओबीसी अभ्यर्थी नहीं मिलने पर अनारक्षित श्रेणी से भरने का नियम है।

बजट में फिट. शौक की नो लिमिट.

एशियन पेंट्स ट्रेक्टर स्पार्क इकोनॉमी इमल्शन

TRACTOR SPARC ECONOMY EMULSION

संपादकीय

आबादी के आंकड़ों के बिना योजनाओं के पहाड़

देश की जनगणना को लेकर सियाी तौर पर कज़ई सवाल व बवाल हैं। हर दस वर्ष में होने वाली जनगणना इस बार करीब चार वर्ष पिछड़ चुकी है लिहाजा नई सरकार के समक्ष लंबित कई प्राथमिकताओं में से एक यह भी है कि हर दशक होने वाली जनगणना को तत्काल अंजाम दिया जाए। दशकीय जनगणना 2021 में होनी थी मगर तब कोविड महामारी के कारण इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया था। अब महामारी का असर न्यूनतम हुए भी दो वर्ष से अधिक समय बीत चुका है लेकिन जनगणना के मोर्चे पर कोई प्रगति होती नहीं दिख रही है। जनगणना के पहले राज्यों को जिलों, तहसीलों और कस्बों आदि की प्रशासनिक सीमाओं को बंद करने का आदेश दिया जाता है लेकिन इसे नौ बार टाला जा चुका है। ताजा जानकारी के मुताबिक जनगणना कराने को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जनकल्याण और मुफ्त उपहारों को लेकर सार्वजनिक तौर पर जबरदस्त बहसों तथा जाति जनगणना की मांगों के बीच यह अस्वाभाविक ही है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने इस महत्वपूर्ण काम को प्राथमिकता नहीं दी जबकि 150 सालों में पहली बार यह काम स्थगित हुआ, वह भी बिना किसी स्पष्ट समय सीमा के। चूंकि ताजा जनगणना डिजिटल रूप में होनी है और इसमें आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में भरना है इसलिए इसे अंजाम देना उतना कठिन और समय खापाऊ नहीं होगा जितना कि अतीत में होता रहा है। दुनिया के सबसे बड़े चुनावों के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होने के बाद डिजिटल जनगणना से भारत की सूचना प्रौद्योगिकी शक्ति की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। इसके बजाय भारत फिलहाल उन 120 देशों में शामिल है जिन्होंने महामारी का हवाला देकर जनगणना की कवायद को रोक रखा है। कई अन्य देशों मसलन चीन, बांग्लादेश और नेपाल ने महामारी के दौरान भी जनगणना की है। भारत उन 44 देशों में शामिल है जिन्होंने अब तक जनगणना नहीं की है। ऐसा करने वाले अन्य देशों में यमन, यूक्रेन, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान तथा सब-सहारा अफ्रीका के देश शामिल हैं जो किसी न किसी तरह के संकट से जूझ रहे हैं। जनगणना जैसी गहन कवायद, भारत जैसे आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता वाले देश में ज्यादा जरूरी है। विडंबना है कि भारत सरकार के पास आबादी को लेकर कोई नई आधिकारिक जानकारी नहीं है। भारत की आधिकारिक आबादी अभी भी 1.2 अरब है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी चीन से अधिक हो चुकी है और 1.4 अरब लोगों के साथ हम दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले देश बन चुके हैं। चूंकि अहम राष्ट्रीय सर्वेक्षण-मसलन खपत सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे, खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कवरेज, प्रवासन के रूझान की समझ आदि जनगणना के ताजा आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। लिहाजा बेहतर होगा कि सरकार स्पष्ट बताए कि जनगणना की योजना कब है। उसे यह भी बताना चाहिए कि क्या अगली जनगणना का समय इससे प्रभावित होगा? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य चीजों के साथ परिसीमन और संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण का क्रियान्वयन भी 2026 के बाद होने जनगणना पर निर्भर है। चूंकि सरकार के पास आबादी को लेकर कोई नया या ठोस आंकड़ा नहीं है इससे यह भी संभव हो सकता कि सरकारों के स्तर पर बड़ी तादाद में घोषित व संचालित की जा रही कल्याण योजना गलत ढंग से लिखित हों, उनकी फंडिंग अपर्याप्त अथवा अनावश्यक हो, यदि यह स्थिति है तो ज्यादा नुकसानदेह है।

नए कानून बनाना सही दिशा में एक कदम लेकिन अनसुलझे मुद्दों पर भी बात हो

■ प्रकाश सिंह

औपनिवेशिक दौर के प्रमुख आपराधिक कानूनों- भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम-की जगह लागू तीन नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में मामले दर्ज होना शुरू भी हो गए हैं। नए कानूनों में एफआईआर, जांच एवं सुनवाई के लिए अनिवार्य समय-सीमा तय कर दी गई है। अब लोग बिना थाना गए ही ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। देश के किसी भी थाने में जीरो एफआईआर दर्ज हो सकेगी। नए बीएनएस में नए अपराधों को शामिल किया गया है, जैसे-विवाह का वादा करके धोखा देने पर 10 साल तक की जेल, नस्ल, जाति-समुदाय, लिंग के आधार पर मॉब लिंगिंग मामले में आजीवन जेल तथा छीन-झपट के लिए तीन साल की जेल। यूएपीए जैसे आतंकवाद-रोधी कानूनों को भी इसमें शामिल किया गया है।औपनिवेशिक विरासत को खत्म करना और कानूनों को वर्तमान समय के अनुरूप बनाने का यह ऐतिहासिक कदम प्रशंसनीय है, पर कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जो अब भी अनसुलझे हैं। औपनिवेशिक काल के कानूनों में 1162 धाराएं थीं, जबकि नए कानूनों में 1059 धाराएं हैं। जाहिर है, अब कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 2,221 धाराओं से जूझना होगा। बीएनएस जैसे मूल कानून को पहले दर्ज किए गए मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए नए कानून के लागू होने से पहले के अपराधों को आईपीसी (भारदंस) के तहत निपटया जाएगा, जबकि नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद किए गए अपराधों को बीएनएस के तहत निपटया जाएगा। हालांकि बीएनएसएस एवं बीएसए जैसे प्रक्रियागत कानूनों को पहले दर्ज किए गए मामलों पर लागू किया जा सकता है। ऐसे में न्यायालय में उन सभी मामलों में विवाद होने की आशंका है, जो नए कानून के लागू होने से पहले दर्ज किए गए थे, लेकिन उनमें नए प्रक्रियात्मक कानून को लागू किया जाएगा। तीनों प्रमुख कानूनों में अलग-अलग राज्यों द्वारा अलग-अलग समय पर संशोधन किए गए हैं। मसलन, सीआरपीसी की धारा 357 (मुआवजा देने के आदेश से संबंधित) में आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों द्वारा संशोधन किए गए। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों द्वारा ऐसे कई संशोधन किए गए। ये संशोधन राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित और लागू किए गए, क्योंकि राज्य की विशेष जरूरतों के लिए ऐसा करना जरूरी पाया गया। नए लागू किए गए कानूनों में राज्यों द्वारा किए गए संशोधनों को शामिल नहीं किया गया है। कई गैर-भाजपा शासित राज्यों ने जब इन नए कानूनों का विरोध किया, तो केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि राज्य सरकारें सुरक्षा संहिता में अपनी ओर से संशोधन करने को स्वतंत्र हैं। नए कानून में गैर-कानूनी कृत्य और आतंकवादी कृत्य की परिभाषा एवं दंड को बीएनएस के दायरे में लाया गया है। तीन वर्ष



से सात वर्ष के बीच कारावास की सजा वाले मामलों में प्रारंभिक जांच का प्रावधान समस्याओं का पिटारा खोल देगा, जहां पुलिस जांच करने से इन्कार कर सकती है, जिससे जनता में असंतोष पैदा होगा। बीएनएसएस की धारा 173(3) में कई अस्पष्टताएं हैं। इस बात की आशंका है कि इससे व्यापक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, कानूनी बिरादरी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत की सुनवाई होगी, तो बचाव पक्ष के वकील, जो अदालत में गवाहों से पूछताछ करेंगे, वे उस आरोपी के सीधे संपर्क में नहीं रह पाएंगे, जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बीएनएसएस कानून के तहत कई प्रगतिशील प्रक्रियाओं के लिए डिजिटल तकनीक अनिवार्य है, जैसे तलाशी की वीडियोग्राफी और ई-कोर्ट कार्यवाही। जबकि अभी थानों, जांच अधिकारियों, अदालतों और जेलों में अब भी आवश्यक बुनियादी ढांचे, उपकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण, प्रणालियों और प्रोटोकॉल का विकास, विशेष तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण जरूरी है। ऐसे में ई-कोर्ट कार्यवाही और इलेक्ट्रॉनिक समन जैसे बीएनएसएस के प्रावधानों को लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा, कई राज्यों में पुलिसकर्मियों को नए कानूनों के बारे में पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया गया है। इससे उन्हें नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में बाधा आएगी और प्रक्रियागत देरी तथा कानूनी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। ऐसी खबरें भी आई हैं कि नए मामले दर्ज करने में पुलिसकर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम तथा आईसीजेएस के साथ इसके इंटरफेस

को भी नए कानूनों के अनुरूप अपडेट नहीं किया गया है, जिससे परिचालन एवं तकनीकी संबंधी गंभीर चुनौतियां पैदा हो रही हैं। जांच के लिए फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य करना स्वागतयोग्य है और विभिन्न जांच प्रक्रियाओं में ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार को मंजूरी देना एक सकारात्मक कदम है। लेकिन प्रशिक्षण के अभाव में इन प्रक्रियाओं को अगर गलत तरीके से निष्पादित किया गया, तो अपराधी दोषमुक्त हो सकते हैं। नए कानून बनाना सही दिशा में एक कदम है, मगर अफसोस केवल इसका है कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जिस गहन चिंतन व व्यापक विमर्श की आवश्यकता थी, जो नहीं किया गया। इंडियन पुलिस फाउंडेशन जैसी संस्था को भी पार्लियामेंट्री कमिटी के सामने पेश होने का समय नहीं मिला। विरोधी दलों को यह शिकायत है कि जब उनके अधिकांश सदस्य सदन से निर्लंबित थे, उस समय इन्हें संसद में पारित किया गया। यह भी एक विरोधाभास है कि हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीन बड़े कानून तो बदल दिए, परंतु पुलिस ऐक्ट, 1861 अब भी देश की जनता के गले की फांस बना हुआ है। नेशनल पुलिस कमीशन ने इसे बदलने की सिफारिश की थी, परंतु अभी तक यह कानून जैसे का तैसा बना हुआ है। नए कानून को लागू करने के लिए जो इम्फास्ट्रक्चर चाहिए, वह अभी उपलब्ध नहीं है। पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने के बारे में बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, यह कहाँ तक सही है, यह तो समय ही बताएगा। संक्षेप में, सही दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है, परंतु जल्दबाजी में।

- साभार: यह लेखक के विचार हैं।

निशाना

खूब हो रही बैठक !



- कृष्णेंद्र राय

चिंतन मंथन चल रहा ।
हो कैसे सुधार ?
रूठ गई है जनता ।
ना करती उपकार ॥
कायाकल्प हो पुनः ।
है ऐसा प्रयास ॥
जनता को नहीं आया पर ।
कार्यशैली रास ॥
खूब हो रही बैठक ।
नहीं निकलता हल ॥
ले रहे संकल्प ।
उत्तम करना कल ॥
कहां हो रही गुलती ।
नहीं समझ ये आया ॥
है लेकिन ये सत्य ।
हो रहा सफाया ॥

- 1989 जापान के एनालॉग शहर में दुनिया का पहला एचडीटीवी प्रसारण शुरू किया गया।
- 2006 पाकिस्तान दा विंची कोड फिल्म पर प्रतिबंध लगाता है क्योंकि इसमें यीशु के बारे में निन्दात्मक सामग्री शामिल है। दा विंची कोड एक 2006 अमेरिकी रहस्य-थ्रिलर फिल्म है, जो जॉन केली और ब्रायन ग्रेजर द्वारा निर्मित और रॉन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित है। पटकथा अकिवा गोल्डस्मैन द्वारा लिखी गई थी और डैन ब्राउन के 2003 में इसी नाम के सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यास से अनुकूलित की गई थी। फिल्म में टॉम

आज का इतिहास

- हैंब्स, ऑट्टो टुट्टो, इयान मैककेलेन, अल्फ्रेड मोल्लिन, जुरगेन प्रांचो, जिन रेनो और पॉल बेट्टनी जैसे कलाकार हैं।
- 2007 म्यांमार और लाओस सीमाओं के पास दक्षिणी चीन में 6.4 तीबता का भूकंप आया, जिससे लोग हताहत हुए।
- 2008 चीन राष्ट्रीय पेट्रोलियम निगम नाइजर में तेल का उत्पादन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करता है। लाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एक चीनी राज्य के स्वामित्व वाली तेल और गैस निगम और चीन की सबसे बड़ी

एकीकृत ऊर्जा कंपनी है। इसका मुख्यालय डोंगचेंग जिला, बीजिंग में है। पेट्रो चाइना की जनक है, जो जुलाई 2014 तक राजस्व के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। ■ 2009 अमेरिकी लेखिका मर्लिन रॉबिन्सन ने अपने उपन्यास होम के लिए फिक्शन के लिए ऑरेंज पुरस्कार जीता। मर्लिन सुमेर रॉबिन्सन एक अमेरिकी उपन्यासकार और निबंधकार हैं। उन्हें 2005 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार और 2012 के राष्ट्रीय मानविकी पदक सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं।



एक समय में एक काम करो , और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमे डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ



ड्रोन आधारित युद्ध में भारतीय सेना ने पीएलए की बढ़त को कम किया, अब इन्हें स्पष्ट दृष्टिकोण जरूरी

■ ले.जन. एच.एस. पनाग (रिटा.)

चीन ने भारतीय सीमा पर 1959 की अपनी दावा रेखा को मजबूत करने के लिए 2020 में जो उपक्रम किए और उनके फलस्वरूप हुए टकराव में दोनों देशों ने सीमा पर सेनाओं का जो भारी जमावड़ा किया उसके बाद मैंने दो लेख लिखे थे. इन लेखों में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से आक्रामक कार्रवाई कर रही चीनी सेना ‘पीपुल्स लिबरेशन आर्मी’ (पीएलए) को रोकने में भारतीय सेना की कमजोरियों को रेखांकित किया था. पिछले चार सालों में इस काबिलियत खासकर ड्रोंनों में काफी प्रगति हुई है। शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता होगा जब सेनाओं में तरह-तरह के ड्रोंनों को शामिल किए जाने की खबर न आती हो. अडाणी, टाटा, रिलायंस कॉर्पोरेट समूहों समेत बड़ी संख्या में छोटे-मझोले उपक्रम और स्टार्ट-अप तक सेना के लिए ड्रोन बनाने की होड़ में शामिल हो गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2030 तक ड्रोन उत्पादन के मामले में ग्लोबल हब बन सकता है. कुछ अनुमानों के अनुसार, 2,000 से लेकर 2,500 ड्रोन सेना में शामिल किए जा चुके हैं और काफी और लाइन में हैं. ड्रोन उनके कल-पुर्जों के उत्पादन और रखरखाव के करारों के मद्दों में करीब 3,000 से लेकर 3,500 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. यह सब सेनाओं को दिए गए आपात तथा विशेष वित्तीय अधिकारों के तहत किया गया है। तो क्या हमारी सेना ने कम-से-कम मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) के मामले में पीएलए की बराबरी कर ली है? संख्या के मामले में अंतर को तो कम कर ही लिया गया है, लेकिन सेना की ताकत बढ़ाने की व्यवस्था के लिहाज से हम अभी उससे मीलों पीछे हैं। क्षा मंत्रालय और सेनाओं ने सभी तरह के यूएवी को आयात की नकारात्मक सूची में शामिल करके अच्छा ही किया है. इसका अर्थ यह हुआ कि यूएवी का उत्पादन देश के अंदर ही ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत किया जाएगा. वैसे, ‘एमक्यू-9बी सी/स्काई गार्डियन’ जैसे यूएवी को इस सूची से अलग रखा जाएगा. लेकिन, भारतीय ड्रोन उद्योग जल्दी ही इस सीमा को भी पार कर लेगा. अडाणी डिफेंस सिस्टम्स

थलसेना और नौसेना से ठेके हासिल करने के बाद मल्टी पे-लोड वाले मझौली ऊंचाई पर उड़ने वाले ‘हर्मीस 900’, या ‘दृष्टि-10’ यूएवी का उत्पादन कर रही है और मजा यह कि यह कंपनी इन्हें इजरायल को वापस निर्यात कर रही है।

सेनाओं ने जरूरतों की फेहरिस्त जारी कर दी है. इसने निजी उद्योगों को सक्रिय कर दिया है और वे विदेशी पार्टनरों को बुलाने में तेजी भी दिखा रहे हैं. ‘डीआरडीओ’ अपनी टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करके निजी क्षेत्र के साथ सहयोग कर रहा है. रक्षा मंत्रालय की पहल ‘इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सिलेंस’ (आइडेक्स) के लाभ भी हासिल होने लगे हैं।अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के मामले में सरकारी और निजी क्षेत्र के निवेश के बिना विश्व स्तरीय ड्रोंनों का उत्पादन नहीं किया जा सकता. केन्द्र सरकार इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सिलेंस, प्रतिरक्षा अधिग्रहण नीति की ‘मेक’ प्रक्रिया, और आर्मी डिजाइन ब्यूरो जैसी व्यवस्थाओं का ‘आर एंड डी’ फंड के लिए इस्तेमाल कर सकती है. हर एक प्रोजेक्ट के लिए सेना को अपने मिशन की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए। अब तक मुख्यतः सामान्य मकसद वाले ड्रोन सेना के इस्तेमाल में लिए गए हैं, जो चीन की वेपन सिस्टम जितनी मजबूत/भरोसेमंद नहीं हैं. सेना के ड्रोन सभी मौसम में दिन और रात में भी काम करने वाले होने चाहिए जो अपेक्षित ऊंचाई तक उड़ान भर सकें और उनमें जवाबी कार्रवाई करने वाली इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था हो और उनका ‘लो सिग्नेचर’ हो यानी उनकी पहचान मुश्किल हो।

‘जनरल स्टाफ कालिटेक्टिव रिक्वायर्मेंट (जीएसक्यूआर) वो आधार है जिसके मुताबिक, ड्रोन काम करते हैं. वजून, रेंज, उड़ान भरने का तरीका, उड़ान की ऊंचाई की सीमा और मजबूती के अलावा ड्रोन का ‘पे-लोड’ (वजन ढोने की क्षमता) भी महत्व



रखता है. ड्रोन पर लगे कैमरे से उसकी तस्वीरों की स्पष्टता, रेंज, दिन/रात/ थर्मल पहचान की क्षमता तय होती है. टैंकों और दूसरे बख्तरबंद वाहनों के लिए उच्च विस्फोटक क्षमता वाले टैंक-रोधी वारहेड की जरूरत होती है. खरीदे गए 20 फीसदी ड्रोन हथियारबंद होते हैं, लेकिन भरे हिसाब से किसी पर वारहेड नहीं लगा है। सेना द्वारा

खरीदे गए 95 फीसदी ड्रोंनों में जवाबी कार्रवाई करने वाली इलेक्ट्रॉनिक किट नहीं लगी है. ये ड्रोन आधुनिक युद्ध में डट नहीं पाएंगे या नाकाम कर दिए जाएंगे. इस समस्या का हम एलएसी के आसपास सामना कर रहे हैं. जरूरत इस बात की है कि सेना विभिन्न तरह के ड्रोंनों के लिए ‘जीएसक्यूआर’ का मोटामोटी निर्धारण करे ताकि कमांड क्षेत्र की जरूरत और काम लागत वाली खोज के मुताबिक, लचीला रख आना सके।फिलहाल सभी सामरिक ड्रोन आर्मी कमांडरों के विशेष वित्तीय अधिकारों और वाइस चीफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ (वीसीओएस) के आपात वित्तीय अधिकारों के तहत खरीदे जा रहे हैं. शीघ्र अधिग्रहण के लिए यह तेज प्रक्रिया उपयुक्त है और इसका लाभ उठाया गया है, लेकिन इसके चलते मानकों में गिरावट, कीमत में अंतर, भंडार में वृद्धि, रखरखाव के महंगे करार, रातोरात उगी कंपनियों द्वारा शोषण आदि के मामले होते हैं।

लंबी रेंज वाले सामरिक और रणनीतिक उपयोग के हथियारबंद या बिना हथियार वाले ड्रोंनों की केंद्रीय खरीद ‘डिफेंस प्रोक्योरमेंट’ या ‘वीसीओएस’ के आपात अधिकारों के तहत करना उपयुक्त होगा. युद्ध में नये प्रयोग के लिए कम रेंज वाले ड्रोन और किट्स की खरीद आर्मी कमांडरों के विशेष वित्तीय अधिकारों के तहत जारी रखी जा सकती है. गुणवत्ता और मजबूती से समझौता करते हुए सबसे नीची बोली लगाने वाले को चुनने की

सरकारी नीति की समीक्षा होनी चाहिए। सेना में रणनीतिक या ऑपरेशन के मकसद पूरे करने वाले हेरोन, हर्मीस और नये एमक्यू-9बी स्काई गार्डियन ड्रोन का उपयोग आर्मी एक्विशन कोर कर रहा है. भारतीय वायुसेना और नौसेना में पूरी संभावना है कि विशेषज्ञ संगठन और कर्मी हैं जो मिशनों के रणनीतिक तथा ऑपरेशन संबंधी जरूरतों के हिसाब से ड्रोंनों का प्रयोग कर रहे हैं. सामरिक उपयोग दोहरी भूमिका निभाने वाले सैनिक करते हैं. यह कामचलाऊ व्यवस्था ड्र्यादातर मजबूरी में लागू की जाती है जब जारी ऑपरेशन के दौरान टेक्नोलॉजी की कमी की तुरंत भरपाई की कोशिश की जाती है।

अधिकतम उपयोग और नियंत्रण के लिए देर-सवेर, विशेषज्ञता हासिल कर चुकी सब-यूनिटों और यूनिटों के गठन की जरूरत पड़ेगी. पिछले दो साल से लड़ रहे यूक्रेन ने दोहरी भूमिका वाले सैनिकों के साथ ड्रोंनों का भरपूर और सफल इस्तेमाल किया है और अब उसने सभी स्तर पर ड्रोंनों का उपयोग करने वाले स्पेशलिस्ट कोर का गठन किया है. इनमें करीबी युद्ध में इस्तेमाल होने वाले बहुत कम रेंज वाले ड्रोन शामिल नहीं हैं. अधिकतर आधुनिक सेनाओं में यूनिट के स्तर पर, संयुक्त आर्मस् ब्रिगेड, डिवीजन या एकीकृत बैटल ग्रुप के स्तर पर ड्रोन सब-यूनिट हैं जो विशेष रेंज वाले ड्रोंनों का संचालन करती हैं. दोहरी भूमिका वाले सैनिक काफी कम रेंज वाले युद्धक ड्रोंनों का लगभग वेपन सिस्टम की तरह इस्तेमाल करते हैं। सेना की यूनिटें सभी सामरिक ड्रोंनों का फिलहाल अपनी जरूरत के हिसाब से एकल रूप में इस्तेमाल कर रही हैं. स्थिति के बारे में सजगता और सूचना का प्रवाह स्टाफ के कई चरणों वाले चैनलों के जरिए होता है. ‘आर्मी इन्फोमेशन ऐंड डिस्पीजन सपोर्ट सिस्टम’ (एआइडीएसएस) की सख्त जरूरत है जिसके साथ सब-सिस्टम्स के लिए विभिन्न स्तर पर इंटरफेस लागू किया जाए जो ऑपरेशन और मैनेजमेंट के स्तर की इन्फोमेशन सिस्टम्स का एकीकरण करे. फिलहाल इस तरह का सिस्टम बनाने काम प्रगति पर है. ‘एआइडीएसएस’ के बिना ड्रोंनों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

- साभार: यह लेखक के विचार हैं।

टैगोर स्कूल में बेटियों के नाम से किया गया पौधारोपण

सिवनी मालवा। नवांकुर संस्था लक्ष्मी समाज कल्याण समिति सिवनी मालवा सेक्टर क्रमांक 05 बासनीया कलां द्वारा टैगोर स्कूल में 9 जुलाई को बेटियों के नाम से पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर कई फलदार पौधे लगाए गए जिसमें आंवला, चीकू, जाम, अशोक, नींबू का पौधारोपण किया गया। पौधारोपण में टैगोर स्कूल प्राचार्य श्रीमती दीपाली अवस्थी, स्कूल संचालक प्रवीण कुमार अवस्थी ब्लॉक समन्वयक हरिदास दायमा, लक्ष्मी समाज कल्याण संस्था अध्यक्ष श्रीमती सुगना लौवंशी, राजेश सराटे, संध्या राठौर, बीएसडब्ल्यू की छात्रा काजल सहित सभी छात्र - छात्राएं उपस्थित थे।



शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने किया मनोहर श्री रेस्टोरेंट का निरीक्षण

नर्मदापुरम। जिला प्रशासन के निर्देशन में एवं शिकायत के आधार पर 09 जुलाई को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश दियावार एवं दल ने मनोहर श्री रेस्टोरेंट का पुनः निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार के अनियमितता पाए जाने पर एवं खुले में खाद्य सामग्री विक्रय होने के कारण नोटिस प्रदान किया एवम बने हुए पोहे का नमूना जांच हेतु लिया गया। मनोहरश्री रेस्टोरेंट पर पहले भी कार्यवाही कर सुधार हेतु कहा गया था परंतु सुधार न होने के कारण पुनः कार्यवाही की गई। साथ ही विक्रेता का लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जा रही है। नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।



ताजियों को लेकर हुई शांति समिति की मीटिंग

सिवनी मालवा। ताजियों का पर्व मनाया जाने को लेकर स्थानीय थाना परिसर में एसडीएम सरोज सिंह परिहार और एसडीओपी राजू रजक की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में एसडीएम सरोज सिंह परिहार में ताजी आधारों से ताजिज निकालने के मागों की जानकारी लेते हुए पूछा कि मार्ग में कहीं कोई परेशानी हो तो प्रशासन और पुलिस को पहले जानकारी दें ताकि उसका समाधान किया जा सके। एसडीओपी राजू रजक ने सभी से कहा कि सिवनी मालवा में परम्परागत तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहारों को मनाने सिलसिला चला आ रहा है। जो आगे भी चलता रहेगा।



अधिवक्ता परिहार बने एमपीईवी में विधायक प्रतिनिधि

इटारसी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक डॉ सीताशरण शर्मा ने अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह परिहार को मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मंगलवार को विधायक डॉ सीताशरण शर्मा ने नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे और आरटीओ विधायक प्रतिनिधि अभिषेक कनौजिया की उपस्थिति में देवेन्द्र सिंह परिहार को नियुक्ति पत्र दिया। अब परिहार विधायक शर्मा की अनुपस्थिति में आवश्यक स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। वहीं, अपनी नियुक्ति पर अधिवक्ता देवेन्द्र परिहार ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा उन्हें जो दायित्व दिया गया है उस पर वह पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि विधायक की ओर से किए जाने वाले कार्यों और उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं को बिजली अधिकारियों के साथ मिलकर हल करने का कार्य किया जाएगा।



मेट्रो एंकर

कलेक्टर जनसुनवाई में 117 आवेदनों पर हुई जनसुनवाई

जनसुनवाई में प्रताड़ना से त्रस्त पति-पत्नी की गुहारें



नर्मदापुरम, दोपहर मेट्रो।

आमजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए आयोजित जनसुनवाई में 117 आवेदन प्राप्त हुए जिनकी कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों ने सुनवाई की। ग्राम सिलारी तहसील इटारसी की अर्निता बाई अपने पति की शिकायत लेकर जनसुनवाई पहुंची। उन्होंने कलेक्टर को प्रस्तुत आवेदन में बताया कि उनका विवाह 8 वर्ष पूर्व रीति रिवाजों से हुआ था। उनके पति उनके साथ मारपीट करते हैं

और दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते हैं। इन सब से परेशान होकर वे अपने माता पिता के साथ मायके में रह रही हैं। कलेक्टर ने एसडीएम को प्रकरण का परीक्षण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में गौतम नगर सोहागपुर के शेख असलम ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उनकी पत्नि उन्हे प्रताड़ित करती है। आए दिन लड़ाई झगडा एवं गाली गलौच करती है। खाना भी नही बनाती है। पति के परिजन भी दहेज एवं मारपीट के झूठे केस में फंसाने की धमकी देते है।

कोठी बाजार की 87 वर्षीय निर्मला मिश्रा ने अपने घर के दोनो ओर चाय वालों, फूल वालों की गुमटियों, टपरियों एवं टेले वालों की शिकायत की कि वे फुटपाथ पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकाने जमा ली है। जनसुनवाई में शास्त्री वाई सोहागपुर के रोहित मिश्रा ने स्कूल शिक्षा में वाहन चालक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। बानापुरा के भूतपूर्व सैनिक भागीरथ प्रसाद ने सिवनीमालवा जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा 3 करोड के भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। नर्मदापुरम की कला कंडारे ने प्रस्तुत आवेदन में बताया कि जुलाई 2023 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात उन्हें पेंशन तथा ग्रेजुटी तो मिल गई लेकिन अन्य क्लेम अभी तक प्राप्त नहीं हुए है। इटारसी के नितान्त गुप्ता ने धोखाधडी की शिकायत करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया कि उनकी बेटी को रक्त की आवश्यकता थी। उन्होने स्वयं अपना रक्त दान किया एवं 1050 रुपये भी दिए। लेकिन उनकी राशि उन्हें वापस लौटा दी गई। लेकिन उनका रक्त देने से इन्कार कर दिया गया। उन्होने उनका रक्त लौटाने की मांग की। गवालटोली के अर्जुन यादव ने बताया कि उन्हें शालेय क्रीडा प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया एवं उनके द्वारा जब सीएम हैल्प लाईन में शिकायत की गई तो नर्मदा कॉलेज ने उक्त शिकायत यह कहकर बंद करवा दी कि वे मानसिक रूप से परेसान रहते है।

किसान संघ ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

मूंग खरीदी को लेकर नाराजगी किसान संघ का धरना प्रदर्शन

सिवनी मालवा/नर्मदापुरम, दोपहर मेट्रो।

मूंग खरीदी को लेकर भारतीय किसान संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पीपल चौक पर लगातार जारी है। आज जिले के पदाधिकारी सहित इटारसी एवं नर्मदा पुरम के तहसील स्तरीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता धरने पर बैठे और उन्होंने शासन की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। किसानों का शोषण बंद करो आदि नारे गुंजते रहे। संघ का कहना है कि जिले के किसानों का आक्रोश निरंतर बढ़ता जा रहा है। किसानों की मांग है की ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन नीति 2024 में आ रही समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंप कर चर्चा कि गई। जिसमे मांग की गई की 1- शासन द्वारा वर्तमान में ग्रीष्मकालीन मूंग के समर्थन मूल्य पर खरीदी के आदेश जारी किए हैं जिसमें पिछले वर्ष शासन द्वारा प्रति हेक्टेयर 16 कुंटल खरीदी की गई थी वही इस वर्ष इसे हटाकर 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है जिसे गत वर्ष की तरह 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर के अनुसार ही खरीदी की जाए।

ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी प्लेट कांटो (बड़े कांटो) से ही की जावे जिस तरह से व्यापारी एवं वेंयरहाउस मालिकों की उपज का तौल बड़े कांटे से किया जावे। प्रत्येक किसानों से प्रतिदिन 25 कुंटल खरीदी को बढ़ाकर 40 कुंटल प्रतिदिन किया जावे। जिसे किसानों को बार-बार खरीदी केंद्र पर आना पड़ेगा। जिससे किसान की अतिरिक्त खर्च में भी बचत होगी। सरकार ने यदि किसानों के हित में तत्काल निर्णय



नहीं लिया तो आंदोलन धीरे-धीरे उग्र रूप धारण करेगा। आज धरना स्थल पर मिसरोद के किसानों ने संगठन को अवगत करवाया कि स्थानीय स्तर पर भी किसान प्रशासनिक आक्रांताओं का शिकार है, उन्हें भवन बनाने के लिए यदि डायवर्सन करवाना हो तो अनेक प्रशासनिक अड़गे डाले जा रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। स्थानीय एसडीएम कार्यालय में प्रशासनिक अराजकता व्याप्त है, वही किसान संघ की मंत्रणा समिति में आज शासन से मांग की गई है कि मूंग खरीदी सीजन में भारी भ्रष्टाचार को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तर पर



अस्थायी रूप से लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की जाये। आज के धरना कार्यक्रम में संभागीय संगठन मंत्री दिनेश शर्मा, प्रांतीय सदस्य सूरज बली जाट, जिला अध्यक्ष देवेन्द्र पटेल के साथ ही ललित सिंह चौहान, हरीश वर्मा, सुभाष साधु, खुमान सिंह, विनोद चौरे, प्रेम नारायण पटेल, श्यामशरण तिवारी, लाला पटेल, रामेश्वर चौरे, मोर सिंह राजपूत, जगदीश कुशवाहा, श्याम किशोर लवंशी श्री राम दुबे, रूप सिंह राजपूत, रतिलाम यदुवंशी विनोद चौरे, भागीरथ साहू, चंद्रशेखर पाल, अजय यादव आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

आंगनबाड़ी संघ ने भी किया समर्थन

आज भारतीय किसान संघ के धरना स्थल पर आंगनवाड़ी सहायिका संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा देवी अहिरवार ने आकर किसान संघ की आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन अपने संगठन की ओर से व्यक्त करते हुए किसानों के हक की इस लड़ाई में आंगनवाड़ी सहायिका संघ द्वारा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने का आश्वासन दिया। उनका कहना है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं किसान है अथवा किसान परिवार से जुड़े हुए हैं।

देश विदेश के साइकिलस्ट ने तय किया 200 किलोमीटर का सफर

नर्मदापुरम, दोपहर मेट्रो।

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं जिला प्रशासन के द्वारा साइकिल सफारी के सहयोग से टूर.डी सतपुड़ा 2024 का आयोजन 05 जुलाई से किया गया था। जिसमें देश एवं विदेश के 16 साइकिलस्ट छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम जिले में 200 किलोमीटर का रोमांचक सफर तय किया। छिंदवाड़ा से शुरू होने वाली सफारी पचमढ़ी में समाप्त हुई। सभी सायकिलस्ट को प्राकृतिक सौंदर्य के बीच चुनौतीपूर्ण चढ़ाई का सामना किया। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मनोरम गंतव्यों के अलावा उन्हें ग्रामीण जीवन व संस्कृति को देखने का मौका भी मिला।

प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग और प्रबंध संचालक मप्र टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि टूर.डी सतपुड़ा के माध्यम से प्रदेश की आफबीट डेस्टिनेशन्स में मौजूद सुंदर परिदृश्य, वन्य जीवन और सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराना चाहते हैं। साइकिल सफारी के



आयोजन का उद्देश्य मध्यप्रदेश को एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के साथ ही क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। छिंदवाड़ा, पातालकोट, तामिया, पचमढ़ी को साइकिलिंग कस्त्युनिटी के मध्य लोकप्रिय भी बनाना है।जिससे इस मार्ग पर नियमित रूप से साइकिलिंग गतिविधि संचालित हो सके। टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ एस के श्रीवास्तव ने बताया कि सभी प्रतिभागी 04 जुलाई को कैप में पहुंचे जहां उनकी ब्रिफिंग हुई।

कचरे की प्रोसेसिंग में बेहतर प्रबंधन एवं मशीनरी का उपयोग हो

नर्मदापुरम। मंगलवार को कलेक्टर सोनिया मीना ने खोजनपुर ट्रेजिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया। वहां उपस्थित चयनित कंपनी के कर्मचारी से ट्रेजिंग ग्राउंड पर कचरे के उचित प्रबंधन एवं उसको विंड रौस करने के लिए की जा रही कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने उक्त कंपनी को तय समय सीमा के भीतर कचरे की प्रोसेसिंग की कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो अधिक मशीनरी एवं श्रमिकों की मात्रा को बढ़ा कर उक्त कार्य करें। कलेक्टर ने कहा है कि कचरा प्रबंधन शहर का प्रमुख मुद्दा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। समय पर काम नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी एवं जरूरत पड़ने पर टेंडर निस्स्त भी किए जा सकते हैं। निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर असवन राम चिरामन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले, एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।



शासकीय आवास में अवैध रूप से रह रहे

शासकीय आवास पर कब्जा करने वालों को हटाने के निर्देश: संभागायुक्त

नर्मदापुरम, दोपहर मेट्रो।

नर्मदापुरम संभागायुक्त केजी तिवारी ने समय सीमा की बैठक में लोक निर्माण विभाग के मुख्य कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए कि वे शासकीय आवास में अवैध रूप से रहने वाले एवं कब्जा न छोड़ने वाले व्यक्तियों पर नियम अनुसार सख्त कार्रवाई करें। संभागायुक्त ने कहा कि शासकीय आवास में अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुल के मकान में भी पता लगाने के निर्देश

दिए की कोई अधिकारी यह कर्मचारी अवैध रूप से तो शासकीय आवास में नहीं रह रहा है। उल्लेखनीय है कि समय सीमा की बैठक में बताया गया था कि शासकीय आवास में रिटायरमेंट के बाद भी कुछ लोग कब्जा करके रह रहे हैं और आवास खाली नहीं कर रहे हैं, और ना ही आवास का किराया दे रहे हैं। संभागायुक्त ने ऐसे लोगों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहां की किराया कर्मचारी की पेंशन से वसूला जाए और रिटायरमेंट के समय एनओसी देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए की उस अधिकारी या कर्मचारी का शासकीय आवास में कब्जा तो नहीं है। उन्होंने जनजाति कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग के आवासों की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने निर्देश दिए की समाचार पत्रों में यदि जिले से संबंधित कोई शिकायत या समस्या प्रकाशित होती है तो उसकी प्रॉपर रिसांस दिया जाए। संबंधित अधिकारी द्वारा उस शिकायत या समस्या की जांच अवश्य की जाए। उन्होंने कहा कि कमिश्नर कार्यालय को मेल से भी यदि कोई

शिकायत कर रहा है तो उसकी भी जांच कर समस्या का निराकरण किया जाए।

उन्होंने सभी संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि उनके पास एक से अधिक जिलों का चार्ज है , तो वे नर्मदा पुरम में रुकने का तिथि अवश्य बताएं। उन्होंने सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आने के लिए निर्देश जारी किया और कहां की सभी विभाग फेस आईडी सिस्टम मशीन लगाए और मशीन पर अपने फेस अटेंडेंस दें। उन्होंने कहा कि जहां सार्थक एप कार्य कर रहा है वहां सार्थक ऐप से अटेंडेंस लिया जाए।

संभागायुक्त ने बताया कि सविनय सुशासन अभियान आगामी शनिवार को प्रातः 6 बजे से शुरू किया जाएगा । इस अभियान के तहत सभी अधिकारी श्रमदान करेंगे, कहीं कचरा डंप है तो उसकी सफाई करेंगे और परिसर को स्वच्छ बनाएंगे। जिस स्कूल में टीचर नहीं आते हैं वहां पर अधिकारी पढ़ाएंगे, उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि सभी स्वास्थ्य केंद्र समय पर खुलें।बैठक में संभागायुक्त ने जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की और कहा कि इस अभियान में जो भी कार्य हाथ में लिए गए हैं उसे समय सीमा में पूरा किया जाए। संभागायुक्त ने कहां की लोकसभा गारंटी केंद्र सक्रिय रूप से कार्य करें, जो प्रकरण आ रहे हैं उन्हें समय सीमा में निराकृत करें।





एम्मा नवारो का गॉफ से हिसाब बराबर, क्वार्टरफाइनल पहुंची

लंदन, एजेंसी

अमरीका की 23 वर्षीय खिलाड़ी एम्मा नवारो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां खेले जा रहे साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विम्बलडन के क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है। नवारो का इस टूर्नामेंट में यह अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है क्योंकि उन्होंने पहली बार यहां अंतिम आठ में प्रवेश किया है। 19वीं वरीय नवारो ने अंतिम-16 राउंड में दूसरी वरीय हमवतन खिलाड़ी कोको गॉफ को 6-4, 6-3 से उलटफेर का शिकार बनाया और पिछला हिसाब भी बराबर किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच यह कुल दूसरी भिड़ंत थी। इससे पहले, दोनों के बीच इसी साल जनवरी में ऑकलैंड ओपन में भिड़ंत हुई थी, जिसमें गॉफ ने जीत दर्ज की थी। अमरीकी खिलाड़ी की सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पाओलिनी से भिड़ंत एम्मा नवारो ने गॉफ से हिसाब बराबर किया।

आगे की राह आसान नहीं

नवारो के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी क्योंकि अब उनका मुकाबला सातवीं वरीय इटालियन खिलाड़ी जैस्मिन पाओलिनी से होगी, जिन्होंने अमरीका की 12वरीय खिलाड़ी मेडिसन कीज को शिकस्त दी थी। इस बीच, कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना को रूसी खिलाड़ी अना कालिसकाया के खिलाफ मुकाबले में वॉकआउट मिला। इस तरह रिबाकिना अंतिम आठ में पहुंची। नवारो के खिलाफ मैच के दौरान कोको गॉफ अपने ही कोचिंग स्टाफ के खिलाफ गुस्से में नजर आई। दरअसल, उनकी कोचिंग टीम उन्हें बाहर से कुछ निर्देश दे रही थी, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। इस कारण वह तनाव में और अपनी कोचिंग टीम पर गुस्सा करते हुए दिखी।

दोपहर मेट्रो

गौतम गंभीर के सामने भारत को फिर आईसीसी ट्रॉफी जितवाना बड़ा चैलेंज

कोहली-रोहित के साथ केमिस्ट्री और नई लीडरशिप तैयार करनी होगी

नई दिल्ली, एजेंसी

गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन गए हैं। बीसीसीआई ने इसकी ऑफिशियल जानकारी दी। गंभीर अब राहुल द्रविड़ की जगह संभालेंगे, जिन्होंने टीम इंडिया के आईसीसी टूर्नामेंट जीतने सूखा का 10 दिन पहले ही खत्म करवाया। उनकी कोचिंग में भारत ने साउथ अफ्रीका को फाइनल हराकर टी-20 वर्ल्ड कप जीता। गंभीर 2027 तक भारत के कोच बने रहेंगे। इस दौरान भारत 5 आईसीसी टूर्नामेंट खेलेगा। गंभीर के सामने इनमें टीम को चैंपियन बनाने की चुनौती है। इसके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर प्लेयर्स के साथ उनकी केमिस्ट्री पर भी नजर होगी।



न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज

हेड कोच के रूप में गंभीर का कार्यकाल श्रीलंका दौरे से शुरू होगा। दौरे पर पहला मैच 27 जुलाई को है। श्रीलंका में टीम 3 वनडे और 3 टी-20 खेलेगी। इसी दौरे से गंभीर के कोचिंग करियर की बुनियाद तय होगी। श्रीलंका दौरा 7 अगस्त को खत्म होगा, इसके बाद 19 सितंबर से टीम इंडिया का बिजी शेड्यूल शुरू हो जाएगा। यहीं से गंभीर के असली चैलेंज भी सामने आएंगे। 2025 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को अगली 3 टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करना होगा। इनमें घरेलू मैदान पर बांग्लादेश से 2 और न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट होंगे। भारत फिलहाल पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, इसलिए टीम से पांचों टेस्ट जीतने की उम्मीद है। नवंबर से जनवरी तक टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट खेलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 के बाद से 4 टेस्ट सीरीज जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया में तो भारत ने लगातार 2 टेस्ट सीरीज जीती है। यानी गंभीर के सामने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है। इसी सीरीज के नतीजे से तय होगा कि भारत लगातार तीसरा डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलेगा या नहीं। 2025 से 2027 तक भारत फिर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका में 3 टेस्ट सीरीज खेलेगा। इस दौरान वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट सीरीज घर में भी रहेंगी। 2027 के डब्ल्यूटीसीफाइनल में पहुंचने के लिए इनमें भी जीत दर्ज करनी ही होगी।

शतक ठोकने वाले अभिषेक शर्मा का खुलासा ‘दबाव में होता हूं तो गिल के बल्ले से खेलता हूं’

नई दिल्ली, एजेंसी

हरारे, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में ताबड़तोड़ अंदाज में 47 गेंद में शतक जड़ने वाले युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बताया कि यह पारी उन्होंने बचपन के मित्र और मौजूदा कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से खेली थी। उन्होंने कहा कि मैं जब भी दबाव में होता हूं को गिल के बल्ले से खेलता हूं। उनका बल्ले मेरे लिए लकी साबित होता है। अभिषेक और शुभमन गिल बचपन के दोस्त हैं। दोनों अंडर-12 से साथ खेल रहे हैं। अभिषेक ने अपने सफर को याद करते हुए कहा,

11-12 वर्ष के बच्चे के तौर शुरू हुआ यह सफर काफी खूबसूरत रहा है। राष्ट्रीय टीम के लिए जब मुझे चुना गया तो सबसे पहला फोन शुभमन का आया। पहले मैच में शून्य पर आउट होने के बाद में दबाव में था और मैंने गिल के बल्ले से खेलने का फैसला किया। अभिषेक ने खुलासा किया कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पदार्पण मैच में शून्य पर आउट होने पर उनके मेंटर युवराज सिंह खुश थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह अच्छी शुरुआत है। लेकिन अब वह मेरे परिवार की तरह खुश होंगे और उन्हें मुझ पर गर्व होगा।



37 साल पुराना रेकॉर्ड तोड़ा: यारोस्लावा ने यह कामयाबी लड़ाई से जूझते यूक्रेन को समर्पित की

पेरिस, एजेंसी

यूक्रेन की 22 वर्षीय युवा लॉग जम्पर (ऊंची कूद) एथलीट यारोस्लावा महुचिख ने रविवार को यहां पेरिस डायमंड लीग में 37 साल पुराना विश्व रेकॉर्ड तोड़ा और अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। यारोस्लावा ने 2.10 मीटर (6.88 फीट) के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उनसे पहले यह विश्व रेकॉर्ड बुल्गारिया की स्टेफका कोस्टाडिनोवा (2.09 मी.) के नाम था, जिन्होंने 1987 में रोम में यह कमाल किया था। इस जीत के बाद वह भावुक हो गई क्योंकि उनका देश पिछले काफी समय से युद्ध की मार झेल रहा है।



यारोस्लावा ने कहा, हम सभी अपने देश, अपने लोगों और सैनिकों के लिए लड़ रहे हैं। हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम हार नहीं मानेंगे और लगातार लड़ेंगे। दुर्भाग्य से यूक्रेन में लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे खुशी है कि मुश्किल समय के बीच मैं अपने देश का नाम एथलेटिक्स के इतिहास में दर्ज कराने में सफल हुई हूं। टोक्यो 2020 की कांस्य पदक विजेता यारोस्लावा ने कहा कि इस प्रदर्शन से उन्हें उम्मीद है कि वे इस बार पेरिस ऑलिंपिक में स्वर्ण पदक जीत सकती हैं।

मनोरंजन बॉलीवुड का कोना

80 से 90 के दशक की चर्चित अभिनेत्री सोनम खान ने फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा से जुड़ा दिलचस्प खुलासा किया है। ‘विजय’ अभिनेत्री की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी, जिसमें उन्होंने दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया था। साल 1988 की इस फिल्म की शूटिंग को याद करते हुए सोनम ने बताया कि कैसे फिल्म निर्माता ने उन्हें डूबने से बचाया था। यह घटना एक महत्वपूर्ण दृश्य के फिल्मांकन के दौरान घटी थी और अगर आदित्य उसमें तुरंत हस्तक्षेप नहीं करते तो यह एक दुखद घटना में तब्दील हो सकती थी। फिल्म में एक यादगार दृश्य दिखाया गया था जहां सोनम को बिकिनी पहननी थी, जो उनके शुरुआती करियर में एक साहसिक पल था। इस सीन की शूटिंग पर विचार करते हुए, सोनम ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान खुलासा किया कि वह उस दिन लगभग डूबने वाली थीं, लेकिन आदित्य चोपड़ा की त्वरित कार्रवाई से उन्हें बचा लिया गया। यश चोपड़ा ने सोनम को बिकिनी सीन के बारे में पहले ही बता दिया था और उन्हें तैराकी सीखने की सलाह दी थी। फिल्म निर्माता की सलाह के बावजूद सोनम ने बिना स्विमिंग सीखे सीन को करने की ठानी। यह दृश्य बेंगलुरु के एक होटल के पूल में शूट किया जाना था और सोनम इसे सिंगल-टैक

अभिनेत्री सोनम के लिए मसीह बने आदित्य फिल्म ‘विजय’ के सेट पर बचाई थी जान



शॉट के रूप में याद करती हैं, जहां उन्हें और ऋषि कपूर दोनों को अलग-अलग दिशाओं से पूल में कूदना था। वाक्ये को याद करते हुए अभिनेत्री ने कहा, मैंने कभी तैराकी सीखने की जहमत नहीं उठाई, और हम बेंगलूर के एक होटल में शूटिंग कर रहे थे। यह एक शॉट वाला दृश्य था जहां ऋषि जी एक बिंदु से चल रहे थे, और मैं दूसरे स्थान से चल रही थी और हम दोनों को पूल में कूदना था। सोनम ने याद करते हुए कहा, मैंने किसी को यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि मुझे तैरना नहीं आता, इसलिए हम दोनों पूल में कूद गए और यह एक ही बार में हुआ। अभिनेत्री ने बताया कि कैसे वह पानी से टकराने पर घबरा गई, तैरने में असमर्थ हो गई और ऋषि कपूर को पकड़ने लगीं। फिल्म करू ने शुरू में सोचा कि उनका संघर्ष दृश्य का हिस्सा था, जब तक कि आदित्य चोपड़ा खतरों को पहचानते हुए उन्हें बचाने के लिए पूरे कपड़े पहनकर पूल में

नहीं कूद गए। सोनम ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मैं पूल में कूद गई और तैरना नहीं जानती थी। मैं सचमुच ऋषि जी को पकड़ रही थी।

हिट फिल्में देने के बावजूद अभिनेता विवेक ओबेरॉय को नहीं मिला काम

बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय को आखिरी बार रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी वेब सीरीज इंडियन फॉर्स में देखा गया था। विवेक अब तक इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दे चुके हैं। उन्होंने मस्ती फैंचाइजी, साथिया, शूटआउट एट लोखंडवाला और ओमकारा जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। अब उन्होंने अपने वर्तमान के फिल्मी करियर की यात्रा के बारे में खुलकर बात की। हाल ही में विवेक ओबेरॉय ने बताया कि कैसे उन्होंने अभिनेता बनने से पहले व्यावसायिक यात्रा शुरू की और अभी भी उसी आय पर निर्भर हैं। विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में एबीपी लाइव को दिए साक्षात्कार में कहा कि मैंने अभिनेता बनने से पहले बिजनेस में कदम रखा था। 15 साल की उम्र में मैंने एक छोटा सा धंधा शुरू किया था, क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल से आया था और मेरे पिता सुरेश ओबेरॉय मुझे 500 रुपये पॉकेट मनी देते थे। मैं लड़कों के बोर्डिंग स्कूल से आया था। मीठीबाई कॉलेज में खूबसूरत लड़कियों को देखा और उन्हें डेट पर ले जाना चाहता था। मुझे हर महीने 500 रुपये दिए जाते थे, लेकिन मैंने एक ही डेट पर सब खर्च कर दिया। उन्होंने आगे कहा, मेरे पिता ने मुझे डाटा और पैसे का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने और ज्यादा जिम्मेदार बनने को कहा। मैं 15 साल का था। मेरा अहंकार आहत था और मैंने अपनी मां से कहा कि मुझे अपने पिता का पैसा नहीं चाहिए, मैं खुद संभाल लूंगा। मैं उस पर अड़ा रहा और अपने पिता से पैसे नहीं लिए, लेकिन मुझे कॉलेज जाने, चाय और रिक्शा यात्रा के लिए पैसे की जरूरत थी। तभी मैंने गलती से काम करना शुरू कर दिया, एक छोटा सा वॉयस गिंग किया, शो कंपोज किए और वहां से थोड़ा-बहुत कमाना शुरू कर दिया। विवेक ने अपने स्टॉक पोर्टफोलियो के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जब मैंने ज्यादा कमाई करना शुरू किया तो मैंने स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू कर दिया, मैंने इसके लिए ब्रोकर्स से ट्रेनिंग ली। मैंने अपना स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो तब शुरू किया जब मैं 16-17 साल का था।



सब्जियों की कीमत बढ़ने से खुदरा महंगाई में होगी वृद्धि

भीषण गर्मी के बाद बारिश से फसलों को नुकसान



मेट्रो बाजार

नई दिल्ली, एजेंसी

आने वाले समय में टमाटर, आलू और हरी सब्जियों के दाम और बढ़ सकते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में बारिश से फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों का कहना है कि मुरादाबाद क्षेत्र में फसलें सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। पहले भीषण गर्मी और अब बारिश की वजह से टमाटर, आलू और प्याज सहित हरी सब्जियों की कीमतें बढ़ने का सीधा असर जून की खुदरा महंगाई पर दिख सकता है। अनुमान है कि 12 जुलाई को जारी होने वाली जून की महंगाई दर 4.80 फीसदी रह सकती है जो मई में 4.75 फीसदी रही थी। 54 अर्थशास्त्रियों के मुताबिक,

महंगाई दर 4.10 फीसदी से लेकर 5.19 फीसदी तक रह सकती है। भीषण गर्मी, फिर बारिश से उत्तरी भारत में कृषि का नुकसान हुआ

था। इससे टमाटर, आलू और प्याज की कीमतें 10 फीसदी से ज्यादा बढ़ी थीं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य आर्थिक सलाहकार कनिका पसरिचा ने कहा, अनाज और दालों के साथ सब्जियों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी ने खाद्य मुद्रास्फोति को उच्च स्तर पर बनाए रखा। इससे अंडे, फलों और मसालों की कम कीमतों का असर भी खत्म हो गया। आने वाले समय में टमाटर, आलू और हरी सब्जियों के दाम और बढ़ सकते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में बारिश से फसलें

बर्बाद हो रही हैं। किसानों का कहना है कि मुरादाबाद क्षेत्र में फसलें सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। किसानों ने बताया, टमाटर के



खेतों में पानी भर जाने से पौधे सूख रहे हैं। इससे किसान अन्य फसलों की खेती के लिए टमाटर की फसल उखाड़ रहे हैं। इससे पहले भीषण

गर्मी से फसलें बर्बाद हुई थीं। किसानों का कहना है कि गर्मी में उन्हें टमाटर की सही कीमतें नहीं मिली थीं। अब जब कीमतें अच्छी है तो बारिश ने उस पर पानी फेर दिया। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि इस महीने से टेलीकॉम कंपनियों की 25 फीसदी तक टैरिफ बढ़ोतरी से आने वाले महीनों में महंगाई पर कम से कम 0.2 फीसदी तक दबाव बढ़ने की संभावना है।

पहली बार खादी एवं ग्रामोद्योग का सालाना कारोबार 1.50 लाख करोड़ रुपये पहुंचा

नई दिल्ली, एजेंसी

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने मंगलवार को कहा, रोजगार में वृद्धि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया। उन्होंने कहा, 2013-14 के बाद से 10 वर्षों में खादी एवं ग्रामोद्योग गतिविधियों में नए रोजगार का सृजन 81 फीसदी बढ़ गया। खादी एवं ग्रामोद्योग का सालाना कारोबार 2023-24 में पहली बार 1.50 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। इस दौरान इसने 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिए। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने मंगलवार को कहा, रोजगार में वृद्धि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया।

उन्होंने कहा, 2013-14 के बाद से 10 वर्षों में खादी एवं ग्रामोद्योग गतिविधियों में नए रोजगार का सृजन 81 फीसदी बढ़ गया। इस अवधि में उत्पादन 315 फीसदी और खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री में 400 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारतीय गेमिंग उद्योग चालू वित्त वर्ष में 20 प्रतिशत बढ़कर 23,100 करोड़ रुपये का हो सकता है। ग्रांट थॉर्नटन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या चीन से आगे निकलकर 44.2 करोड़ पहुंच गई है। रिपोर्ट में गेमिंग उद्योग के लिए व्यापक आचार संहिता की वकालत की गई, जो जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नैतिक व्यवहार के मानक निर्धारित करती हो।

पुलिस लाइन नेहरू नगर की घटना, पुलिस जांच में जुटी

ट्रैफिक के एसआई ने 315 बोर की रायफल से खुद को मारी गोली, मौत

भोपाल, दोपहर मेट्रो। कमला नगर थाना क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन नेहरू नगर में आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास ट्रैफिक पुलिस के एसआई ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कुछ वर्षों से वह तनाव में थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल कीड टीम से घटनास्थल का निरीक्षण कराने के बाद एसआई का शव पीएम के लिए मर्चूरी भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

एसपी चंद्रशेखर पांडे ने बताया कि 55 साल के योगेंद्र यादव नेहरू नगर पुलिस लाइन में रहते थे। वे ट्रैफिक में एसआई थे। उनके परिवार में माता पिता के अलावा, पत्नी और तीन बेटे हैं। यहां पुलिस लाइन में वह संयुक्त परिवार में रह रहे थे। परिजन ने पुलिस को बताया कि सुबह धमाके की आवाज आई और वह सीड़ियों के तरफ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देखा तो योगेंद्र यादव खून से लतपाथ पड़े थे और उनके पास रायफल पड़ी हुई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल की टीम से घटनास्थल का निरीक्षण कराने के बाद शव पीएम के लिए भेज दिया।

पत्नी थी कैंसर से पीड़ित

पुलिस ने परिजन से प्राथमिक पूछताछ की तो पता चला कि योगेंद्र यादव की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने के कारण पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। इसी को लेकर वह तनाव में थे। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ दिन से वह ड्यूटी भी नहीं जा रहे थे।



सीड़ियों पर बैठकर गर्दन पर लगाई नाल और किया फायर

पुलिस की प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई कि योगेंद्र यादव 315 बोर की रायफल लेकर सीड़ियां पर बैठे थे। इसके बाद उन्होंने रायफल की नाल गले पर लगाई और ट्रिगर दबा दिया। काफी पास से गोली लगने के कारण उनकी गर्दन और सिर का हिस्से में गंभीर चोट थी। दीवार में भी आसपास खून और मांस के छींटे पड़े नजर आए हैं।

बुजुर्ग पर हमला करने वाला निगरानी बदमाश गिरफ्तार 3 माह से फरार था

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

ऐशबाग इलाके में 72 साल के बुजुर्ग पर प्राणघातक हमला करने वाले निगरानी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने रुपये नहीं देने पर बुजुर्ग व्यक्ति के पर उस्तरे से हमला फरार हो गया था। पुलिस पिछले तीन महीने से उसकी तलाश कर रही थी। आरोपी के खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा संगीन अपराध शहर के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक बाबू सलाम (72) बाग उमरावदूल्हा ऐशबाग में रहते हैं और किराए पर ठेले चलवाने का काम करते हैं। बीती 14 अप्रैल की सुबह करीब दस बजे उनकी भतीजा फैज उर्फ कल्लू उनके पास पहुंचा और रुपयों की मांग करने लगा। फैज ग्वाल मोहल्ल रेशनपुरा का रहने वाला है और अरेरा हिल्स थाने का निगरानी बदमाश है। बाबू सलाम ने भतीजे को पांच सौ रुपए दिए वह ज्यादा रुपयों की मांग करने लगा। उन्होंने ज्यादा रुपये देने इंकार किया तो फैज ने उस्तरे से उनकी गर्दन पर वार कर दिया। बाबू ने अपना बचाव करने का प्रयास किया तो उस्तरा उनके गाल पर लगा, जिससे खून बहने लगा। बाबू ने शोर मचाया तो उनके परिजन और आसपास के लोगों ने बीच-बचाव किया। उसके बाद फैज वहां से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट, चाकूबाजी, अड़िबाजी और हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। घटना के बाद आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई थी। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी फैज उर्फ कल्लू खान (22) निवासी ग्वाल मोहल्ल रेशनपुरा को गिरफ्तार कर लिया है।

ललितपुर जा रही महिला यात्री का बस में हुआ प्रसव डायल 100 ने प्रसूता और नवजात को पहुंचाया अस्पताल

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

इंदौर से ललितपुर उत्तर प्रदेश जा रही एक महिला यात्री का बस में प्रसव हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बैरिसिया थाने की डायल 100 ने प्रसूता और नवजात को संकुशल अस्पताल में भर्ती कराया। पीट को त्वरित सेवा मिलने पर परिजन ने डायल 100 सेवा का आभार मानते हुए सराहना की है। जानकारी के अनुसार मंगलवार तड़के करीब तीन बजे राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल 100 को सूचना मिली कि बैरिसिया थातांतर्गत ग्राम बरखेड़ा मौजी के पास एक महिला बस यात्री का प्रसव हुआ है। प्रसूता महिला एवं नवजात बच्चे को अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना मिलते ही बैरिसिया थाना क्षेत्र की डायल 100 को मदद के लिए मौके पर रवाना किया गया है।

नाबालिग को कमरे में बंद कर किया बलात्कार

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

शहर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने नाबालिग को घर बुलाया और कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी दो महीने तक नाबालिग को डरा-धमकाकर उसका शोषण करता रहा। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि करीब 2 महीने पहले वह घर अकेली थी। तभी बस्ती में रहने वाला कुलदीप उसके घर आया और उसे अपने घर ले गया जहां दुष्कर्म किया।



मेट्रो एंकर नरेला जोड़ से कुछ दूरी पर स्कूल के सामने हादसा

दुर्घटना: सड़क पार कर रहे युवक को बाइक सवार ने मारी टक्कर, मौत

भोपाल, दोपहर मेट्रो। अयोध्या नगर थाना क्षेत्र स्थित नरेला जोड़ से कुछ दूरी पर क्वीन मेरी स्कूल के सामने मुख्य बायपास पर अज्ञात बाइक सवार ने सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसा बीती रात करीब सवा 12 बजे के आसपास का है। बाइक से टककर लगने के कारण उसे गंभीर चोट आई थी। उसे पीपुल्स अस्पताल ले जाया गया, वहां आज सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पीएम के लिए मर्चूरी भेज दिया है।

पुलिस टक्कर मारने वाले बाइक सवार का पता लगा रही है। पुलिस के अनुसार जितेंद्र पिता अशोक लोधी (20) क्रशर बस्ती, शंकर खदान, अयोध्या नगर में रहता था और प्राइवेट काम करता था। मंगलवार देर रात वह नरेला जोड़ होता हुआ पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था। नरेला जोड़ से थोड़े आगे मुख्य बायपास पर क्वीन मेरी स्कूल के पास वह दौड़कर सड़क पार कर रहा था। तभी बायपास से गुजर रही तेज रफ्तार बाइक के चालक ने लापरवाहीपूर्वक बाइक चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से जितेंद्र सड़क पर गिर गया था, जबकि बाइक सवार भी गिरा था। सड़क पर गिरे बाइक सवार ने बाइक उठाई और भाग निकला। इधर, गंभीर रूप से घायल जितेंद्र को एंबुलेंस पीपुल्स अस्पताल लेकर पहुंची थी। वहां इलाज के दौरान तड़के करीब पौने तीन बजे उसकी मौत हो गई।



नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या



भोपाल, दोपहर मेट्रो।

गोविंदपुरा थाना क्षेत्र स्थित टू ए साकेत नगर में मंगलवार सुबह एक महिला ने फांसी लगा ली। नजर पड़ते ही पति उसे फंदे से उतारकर एम्स अस्पताल लेकर पहुंचा था, वहां रात करीब 11 बजे के आसपास डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पीएम के लिए मर्चूरी भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामला नव विवाहिता से जुड़ा होने के कारण मर्ग डायरी एसीपी गोविंदपुरा को सौंपी जाएगी। पुलिस के अनुसार पूजा थापड़ पति निखिल दुबे (34) श्री ए साकेत, गोविंदपुरा में रहती थीं। पति ने निखिल दुबे ने पुलिस को बताया कि मंगलवार सुबह करीब 9 बजे के आसपास उसने अपने कमरे में दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। नजर पड़ते ही निखिल उसे फंदे से उतारकर पास ही स्थित एम्स लेकर पहुंचा डूथा। एम्स में उसका इलाज चल रहा था और रात करीब 11 बजे के आसपास डॉक्टर ने पूजा को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि पूजा और निखिल की शादी दो साल पहले हुई थी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है।

युवक ने फांसी लगा कर की आत्महत्या



भोपाल, दोपहर मेट्रो।

टोंटी नगर थाना क्षेत्र स्थित पंचशील नगर में एक युवक ने फांसी लगा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके पास से सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पीएम के लिए मर्चूरी भेज दिया है। एसआई चंद्रभान गुर्जर ने बताया कि दिलीप तपकाले पिता देवीदास (28) पंचशील नगर, में रहता था और प्राइवेट काम करता था। बीती रात करीब सवा 12 बजे के आसपास उसने फांसी लगा ली। नजर पड़ते ही परिजन उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए थे। वहां डॉक्टर ने प्राथमिक जांच में ही उसे मृत घोषित करते हुए पुलिस को सूचना दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दिलीप का शव पीएम के लिए मर्चूरी भेज दिया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है।

आरसी कार्ड रिन्यू कराने के नाम पर एक लाख 56 हजार की ठगी

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

हबीबगंज क्षेत्र निवासी एक महिला से आरसी कार्ड रिन्यू कराने के नाम पर 1 लाख 56 हजार 756 रुपए की ठगी की गई है। पीड़िता ने साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत कही है। पुलिस ने बताया कि बीडीए कॉलोनी शिवाजी नगर में निवासी सुनीता गर्ग को आरसी कार्ड रिन्यू कराना था। उन्होंने 14 फरवरी को कस्टमर केयर से पूछताछ की, तो उन्हें अव्वल ऐप डाउनलोड करके कार्ड रिन्यू कराने की सलाह दी गई। ऐप डाउनलोड करने के बाद जालसाज ने उन्हें 18500 डायल करने को कहा। नंबर डायल करते ही खाते से पैसे कट गए पर मैसेज नहीं आया। इस पर जालसाज ने उन्हें दूसरे खाते से वही नंबर डायल करने को कहा। पीड़िता द्वारा नंबर डायल करते ही एक बार में 98200 और दूसरी बार 40 हजार रुपए कट गए।

